

तर्कहीन व छत्तीसगढ़ की दुर्गति करने वाला बजट, रोजगार, शिक्षा, कृषि, महिला सुरक्षा किसी पर कोई प्रावधान न होना दुर्भाग्यपूर्ण-सुशील मौर्य

छत्तीसगढ़ को विकसित करने का नहीं, भाजपा ने अपने मुनाफखोरी का पेश किया बजट...

बस्तर के विकास हेतु सिर्फ सब्जबाग, साय सरकार का तीसरा बजट भी निराशाजनक, ओपी चौधरी ने जनता को तोपी पहनाने पेश किया बजट

जगदलपुर (विश्व परिवार)। बस्तर जिला कांग्रेस कमेटी शहर अध्यक्ष सुशील मौर्य ने छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री ओपी चौधरी द्वारा मंगलवार को विधानसभा में वित्तीय वर्ष 2026-27 का बजट पेश किए जाने के बाद तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा बजट में रोजगार, शिक्षा, कृषि, महिला सुरक्षा किसी पर कोई प्रावधान न होना

बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है किसानों की अपेक्षाओं पर खरा नहीं उतरने वाला बजट है प्रदेश सरकार खुद को किसानों का हिस्सेदार बताती है, लेकिन समर्थन मूल्य पर धान खरीदने में सरकार की ओर से आना-कानी की जाती है और नए-नए नियम व शर्तें लागू कर किसानों को अपनी उपज बेचने से वंचित किया जाता है प्रदेश की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार किसान हैं, लेकिन प्रस्तुत बजट में किसानों के लिए कोई ठोस और भरोसेमंद प्रावधान नजर नहीं आना दिशाहीन बजट में आता है छत्तीसगढ़ को विकसित करने का नहीं, भाजपा ने अपने मुनाफखोरी का पेश बजट किया है इस बजट मुनाफ और संसाधनों की लूट का संकल्प है आयनर स्टील और कृषि आधारित इकाइयों के संरक्षण के लिए कुछ नहीं है। अनियमित और संविदा कर्मचारियों के नियमितीकरण का वादा भी पूरा नहीं हुआ। रसोइया संघ और महिलाओं के लिए भी बजट में कोई



विशेष प्रावधान नहीं है यह बजट महिलाओं के लिए निराशाजनक बजट है। महिला सुरक्षा और रोजगार के लिए कोई विशेष पैकेज नहीं है। रानी दुर्गावती योजना भी अस्पष्ट है। 500 रुपये में रसोई गैस सिलिंडर के वादे के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया साय सरकार का तीसरा बजट भी जनता को निराश करने वाला बजट है वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने जनता को तोपी पहनाने पेश वाला बजट पेश किया है। शहर जिला कांग्रेस अध्यक्ष सुशील

मौर्य ने कहा वित्त मंत्री ओपी चौधरी का बजट वाले भाषण में बस्तर के विकास के लिए सिर्फ सब्जबाग दिखाए गए। क्योंकि इस बजट में पेश वादों को पूरा करने वाले प्रावधान निराश करने वाले रहे हैं पिछले बजट में घोषित 20 हजार शिक्षकों की भर्ती में से कितने की भर्ती हुई ओपी चौधरी पहले ये बताएं? भाजपा के विधानसभा चुनाव वादे, पांच साल में एक लाख युवाओं को नौकरी देने, बजट में नए स्कूल, महाविद्यालय, कौशल उन्नयन, सिंचाई बांध या महिला स्व-सहायता समूह के रोजगार के लिए कुछ नहीं है। उद्योगों के विकास के लिए भी कोई प्रावधान नहीं दिखा। युवाओं को बेरोजगारी भत्ता और छात्राओं को मुफ्त यातायात के वादों पर भी वित्त मंत्री ने कुछ नहीं किया है। घरेलू बिजली उपभोक्ताओं के लिए मात्र 80 करोड़ रुपये का प्रावधान 200 यूनिट मुफ्त बिजली योजना बंद करने का संकेत है। डीएड अभ्यर्थियों की भर्ती, आंगनवाड़ी

वहनों और रसोइया संघ के लिए भी बजट में कुछ नहीं है। अनियमित कर्मचारियों को नियमित करने और 56 हजार शिक्षकों के खाली पदों को भरने के लिए भी कोई प्रावधान नहीं किया गया। भर्ती परीक्षा की एजेंसी को मजबूत करने वाली भाजपा सरकार बताए कि एक वर्ष में कितनी नौकरियां दी जाएंगी पर इस पर कोई स्पष्टता नहीं है वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने बजट के भाषण में कहा जगदलपुर में एक सुपर-स्पेशलिटी अस्पताल योजना पर अभी तक काम ही चल रहा है। जबकि सुपर स्पेशलिटी कॉन्वेंशनल अस्पताल में लूट का आरोबार चल रहा है किसी भी जनप्रतिनिधियों ने आवाज तक नहीं उठाई और आज बजट में इन क्षेत्रों के समुदायों तक गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाने की बात की जा रही है कुल मिलाकर वित्त मंत्री ओपी चौधरी के द्वारा पेश बजट तर्कहीन व छत्तीसगढ़ की दुर्गतिकरणे वाला बजट है।

सूरजपुर की उम्मीदों पर फिरा पानी, जिला कांग्रेस अध्यक्ष शशि सिंह ने बजट को बताया छलावा

एसएमएफजी इंडिया क्रेडिट पशु विकास दिवस के माध्यम से 'सर्वोत्तम सेवा' में अग्रणी; 1.55 लाख ग्रामीणों पर उत्पन्न किया सकारात्मक प्रभाव

सरकार ने जिले को विकास के नवशे से मिटाया



सूरजपुर ब्यूरो (दैनिक विश्व परिवार) छत्तीसगढ़ की भाजपा सरकार द्वारा आज पेश किए गए वित्तीय वर्ष 2026-27 के बजट पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए सूरजपुर जिला कांग्रेस अध्यक्ष शशि सिंह ने इसे पूरी तरह दिशाहीन और जनविरोधी करार दिया उन्होंने कहा कि यह बजट केवल विज्ञापनों और आंकड़ों की बाजीगरी है जिसमें छत्तीसगढ़ के आम आदमी, किसान और युवाओं के लिए कुछ भी नया नहीं है। सूरजपुर की घोर उपेक्षा: शशि सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री का गृह संभाषण से होने के

बावजूद, सूरजपुर जिले के लिए इस बजट में कोई भी बड़ी स्वास्थ्य सुविधा या नए मेडिकल कॉलेज की ठोस पहल नहीं दिखी। किसान और ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर चोट: अध्यक्ष ने कहा कि सूरजपुर के किसान अपनी मेहनत के हक के लिए तरस रहे हैं बजट में न तो खाद-बीज की किल्लत दूर करने का कोई रोडमैप है और न ही धान के बीसकों को लेकर कोई स्पष्ट नीति सरकार ने किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के बजाय

कर्ज के दलदल की ओर धकेल दिया है। महंगाई पर सरकार का 'मौन' ब्रत: अध्यक्ष ने कहा कि महतारी वंदन योजना के नाम पर एक हाथ से पैसे देकर महंगाई और टैक्स के जरिए दूसरे हाथ से जनता की जेब काटी जा रही है। रसोई गैस, पेट्रोल और जरूरी वस्तुओं की कीमतों को कम करने की दिशा में बजट पूरी तरह मौन है। यह बजट विकसित छत्तीसगढ़ का नहीं, बल्कि 'विज्ञापनी छत्तीसगढ़' का बजट है। भाजपा सरकार ने एक बार फिर साबित कर दिया कि उनकी प्राथमिकता में आम जनता नहीं बल्कि केवल बड़े पूंजीपति हैं सूरजपुर की जनता इस अन्याय का जवाब देने वाले समय में जरूर देगी।

रायपुर : भारत की अग्रणी एनबीएफसी में से एक एसएमएफजी इंडिया क्रेडिट ने 14 फरवरी 2026 को अपनी प्रमुख पशु कल्याण एवं ग्रामीण आजीविका पहल, पशु विकास दिवस के आठवें संस्करण का सफल समापन किया। 'सर्वोत्तम सेवा: पशु, परिवार और प्रगति' की थीम पर आधारित इस पहल ने पशुओं के स्वास्थ्य, परिवार के कल्याण एवं स्थायी प्रगति को बढ़ावा देकर समग्र ग्रामीण विकास के लिए संगठन की प्रतिबद्धता को मजबूत बनाया। 2014 में लॉन्च किया गया पशु विकास दिवस पशु मालिकों को निःशुल्क वेटेरीनरी सेवाएं और विशेषज्ञों का मार्गदर्शन उपलब्ध कराकर उनकी स्वास्थ्यसेवा संबंधी ज़रूरतों को पूरा करता है। पिछले सालों के दौरान यह पहल देश के सबसे बड़े एक दिवसीय पशु कल्याण प्रोग्रामों में से एक के रूप में उभरी है। एसएमएफजी इंडिया क्रेडिट ने 1.55

लाख से अधिक जिंदगियों पर सकारात्मक प्रभाव उत्पन्न किया है, जिसके तहत तकरीबन 1.4 लाख पशुओं का इलाज किया गया, 14,000 से अधिक लोगों को स्वास्थ्यसेवाओं में सहयोग दिया गया, इससे 30,000 से अधिक परिवारों को लाभ हुआ। इस पहल का संचालन 16 राज्यों में 510 एसएमएफजी ग्रामशक्ति शाखाओं में किया गया, जो ग्रामीण भारत में कंपनी की गहरी पहुंच को दर्शाता है। छत्तीसगढ़ में पशु विकास दिवस का आयोजन 17 लोकेशनों में किया गया, जिसके तहत तकरीबन 4000 पशुओं को स्वास्थ्य देखभाल सेवाएं मुहैया कराई गईं और 650 से अधिक परिवारों को लाभ हुआ। हर कैम्प में स्थानीय वेटेरीनरी डॉक्टरों ने पशुओं की निःशुल्क जांच की, पशुओं के लिए मुफ्त दवाएं बांटी गईं, टीकाकरण किया और दुधारू पशुओं की उत्पादकता बढ़ाने के लिए सलाह दी गई।

इस पहल के सफल समापन पर बात करते हुए श्री रवि नारायणन, मैनेजिंग डायरेक्टर एवं चीफ़ एग्ज़िक्यूटिव ऑफिसर, एसएमएफजी इंडिया क्रेडिट ने कहा, "सर्वोत्तम सेवा सर्वोच्च मानकों की सेवाएं उपलब्ध कराने के बारे में हमें जहां सहानुभूति के साथ प्रभाव और इरादे का संयोजन गहरा प्रभाव उत्पन्न करता है। ग्रामीण भारत में पशुओं का स्वास्थ्य, परिवारों की सुरक्षा और आर्थिक प्रगति एक दूसरे के साथ गहराई से जुड़े हैं। पशु विकास दिवस पशुओं की देखभाल, आजीविका के सशक्तीकरण और समुदायों के कल्याण को समर्थन देकर इस सिस्टम को मजबूत बनाने का हमारी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। इस पहल के ज़रिए हमारा उद्देश्य ऐसे स्थायी परिणामों का निर्माण करना है जो किसान के परिवार को सशक्त बनाएं और बुनियादी स्तर पर समावेशी विकास को बढ़ावा दें।"

कलर्स के 'लाफ्टर शेफ्स अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट' में वाइल्ड कुकिंग के जंगल में आपका स्वागत है!

कलर्स के शो 'लाफ्टर शेफ्स अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट' की किचन इस बार जंगल थीम में तब्दील हो गई, जहां कुकिंग का हंगामा हंसी से भरे सफरी में बदल गया। एनन की जगह जानवरों के अंदाज ने ली और किचन का फ्लोर जंगल में बदल गया, जहां सिर्फ एक ही नियम था-हंसी या हंसाओ! जंगल स्पेशल एपिसोड में प्रतिभागियों ने अपने वाइल्ड अंदाज को अपनाया अंकिता लोखंडे बिल्ली बनकर मंच पर आईं, सुधेश लेहरी जंगल सफरी गाई के रूप में नजर आए, जन्नत जुबैर ने केंचुए का किरदार निभाया, कृष्णा उंट बने, सामर्थ घोड़े के रूप में आए, भारती तिल्ली की तरह इधर-उधर उड़ती दिखीं, जबकि बाकी टीम भी उतने ही मजेदार और अनोखे अवतारों में दिखाई दी। इस वाइल्ड मस्ती में व्यूटनेस का तड़का तब लगा जब कटेस्टेंट्स अपने असली पालतू जानवरों को लेकर पहुंचे। करण कुंद्रा और तेजस्वी प्रकाश अपने डॉस मजनु और डकु को लेकर आए, अंकिता ने अपनी बिल्ली माऊ से सबको मिलवाया, अर्जुन बिजलानी अपनी कैट अंता के साथ आए, जबकि अली गौनी अपने डॉग रेम्बो को लेकर पहुंचे। कुछ देर के लिए किचन पालतू जानवरों का पैराडिस बन गई और दिल पिघल गए, भले ही काउंटर पर कुकिंग का हंगामा जारी रहा। जंगल तब और जिंदा हो उठा जब तेजस्वी ने अपने आइकॉनिक ट्रैक 'मैं नागिन- पर नागिन-स्टालिन एंटी की। सर्प क्रीन के अवतार में उन्होंने अपना मशहूर नागिन डायलॉग बोला-इस बार 'लाफ्टर शेफ्स' के खास टिक्के के साथ। लेकिन इससे पहले कि वह ज्यादा आगे बढ़ पातीं, कृष्णा अभिषेक ने रोस्ट करते हुए चुटकी ली कि तेजस्वी घंटों मेकअप में बैठती हैं, फिर लेट हो जाती हैं और उसके बाद रोने लगती हैं।

स्वयं सेवी संस्था पथ प्रदर्शक का मिशन रक्तदान हिंदुस्तान के तहत केन्द्रीय चिकित्सालय बिश्रामपुर में रक्तदान शिविर आज

रक्तदान को हिन्दुस्तान में जन आंदोलन बनाने का प्रयास में लगी संस्था - बम्रेन्द्र

सूरजपुर ब्यूरो (दैनिक विश्व परिवार) हिन्दुस्तान में रक्तदान को जन आंदोलन बनाने के प्रयास में औरंगाबाद, बिहार की स्वयं सेवी संस्था पथ प्रदर्शक द्वारा लगातार कई तरह के रक्तदान जागरूकता का अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें प्रमुख रूप से एक अभियान है मिशन रक्तदान हिंदुस्तान इस अभियान के तहत संस्था के संस्थापक सह सचिव बम्रेन्द्र कुमार सिंह रक्तदान का अलख जगाने एवं रक्तदान को जन आंदोलन बनाने के



उद्देश्य से देश के अलग अलग राज्यों के भिन्न भिन्न शहरों में वहां की स्थानीय संस्था के सहयोग से रक्तदान शिविर आयोजित कर रहे हैं। इसी कड़ी में पथ प्रदर्शक द्वारा आज

हॉस्पिटल बिश्रामपुर में प्रातः दस बजे से दोपहर तीन बजे तक शिविर का आयोजन सुनिश्चित किया गया है। रक्तसेवक बम्रेन्द्र ने कहा की हिंदुस्तान में रक्तदान को जन आंदोलन बनाने का प्रयास है मेरा, ताकि ब्लड बैंक में रक्त की किल्लत न हो और रक्त की कमी के कारण किसी की जान न जाए। उन्होंने बताया कि संस्था पथ प्रदर्शक द्वारा अभी तक दो सौ से ज्यादा रक्तदान शिविर का आयोजन किया जा चुका है। मिशन रक्तदान हिंदुस्तान के तहत यह नौवां राज्य का इक्कीसवां रक्तदान शिविर है।

राज्य बजट किसान एवं युवाओं के उज्वल भविष्य की दिशा में महत्वपूर्ण कदम-कपिल पांडेय

गोपाल सिंह विद्वाही



सूरजपुर ब्यूरो (दैनिक विश्व परिवार) छत्तीसगढ़ विधानसभा में प्रस्तुत राज्य बजट पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए भाजपा नेता कपिल पांडेय ने कहा कि यह बजट प्रदेश के किसानों और युवाओं को केंद्र में रखकर तैयार किया गया दूरदर्शी एवं विकासोन्मुख बजट है, जो आत्मनिर्भर छत्तीसगढ़ के निर्माण की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। उन्होंने कहा कि किसानों के लिए कृषि पंपों पर मुफ्त बिजली, ग्रामीण अधोसंरचना के विस्तार तथा कृषि सुविधाओं में वृद्धि से खेती

को मजबूती मिलेगी और किसानों की आय बढ़ाने में सहायता मिलेगी। सरकार द्वारा ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाने के लिए किए गए प्रावधान गांव और किसान दोनों के विकास को नई गति देंगे। किसानों की आय बढ़ाने वाला बजट-अजय

अग्रवाल(अज्जू) छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा प्रस्तुत 1.72 लाख करोड़ के बजट पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए किसान मोर्चा जिला महामंत्री अजय अग्रवाल ने कहा कि यह बजट किसानों, ग्रामीण अर्थव्यवस्था एवं कृषि श्रमिक

परिवारों को सशक्त बनाने वाला है। उन्होंने कहा कि किसानों के लिए ब्याज मुक्त निधि हेतु 350 करोड़, सहकारी समितियों के सुदृढीकरण, सिंचाई एवं ग्रामीण विकास योजनाओं के प्रावधान से खेती को मजबूती मिलेगी। भूमिहीन कृषि मजदूर परिवारों के लिए 7600 करोड़ का

प्रावधान ग्रामीण समाज के कमजोर वर्गों के लिए बड़ा सहारा बनेगा। श्री अग्रवाल ने कहा कि सरकार द्वारा कृषि और गांव केंद्रित योजनाओं को प्राथमिकता देना किसानों की आर्थिक स्थिति सुधारने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।

शहरी विकास और

अधोसंरचना को नई गति देने वाला बजट-अरविंद मिश्रा राज्य बजट पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए भाजपा मंडल अध्यक्ष अरविंद मिश्रा ने कहा कि यह बजट शहरी विकास, सड़क निर्माण एवं नागरिक सुविधाओं के विस्तार को नई गति देने वाला है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री सड़क योजना हेतु 200 करोड़, शहरों को जोड़ने वाली परियोजनाएं, शहरी अधोसंरचना एवं एजुकेशन सिटी जैसे प्रावधान प्रदेश के नगरों को आधुनिक स्वरूप प्रदान करेंगे। नगरीय क्षेत्रों में विकास कार्यों से व्यापार, निवेश और रोजगार के अवसर बढ़ेंगे।

संक्षिप्त समाचार

समय पर निर्माण कार्य एजेंसियां कार्य को करे पूर्ण - विजेंद्र सिंह पाटले



सूरजपुर ब्यूरो (दैनिक विश्व परिवार) सूरजपुर जिले के कलेक्टर एस. जयवर्धन के निर्देश पर जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी विजेंद्र सिंह पाटले के अध्यक्षता में समग्र शिक्षा एवं पीएमश्री के स्कूलों के निर्माण कार्य की समीक्षा संबंधित एजेंसियों की उपस्थिति में की गई। निर्माण एजेंसी लोक सेवा यांत्रिकी, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल, क्रेडा, जनपद पंचायत एवं नगर पंचायत के अधिकारियों की उपस्थिति में सभी निर्माण कार्यों का विद्यालयवार समीक्षा किया गया तथा 15 एवं 31 मार्च का समय देकर कार्य पूर्ण करने का निर्देश दिया गया। मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री विजेंद्र सिंह पाटले ने बालिका शांतालय को 8 मार्च से पहले पूर्ण करने का कड़ा निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि पीएमश्री विद्यालय विभाग के प्राथमिकता में से है, और इसका मॉनिटरिंग राज्य और केंद्र स्तर से किया जा रहा है, सभी एजेंसियां समय पर निर्माण कार्य सुनिश्चित करें। यदि टेकेदार कार्य में विलंब कर रहे हैं तो नोटिस जारी कर कार्यवाही करें। कार्यों में किसी भी प्रकार की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने सभी जनपद सीईओ को पंचायत स्तर पर निर्माण कार्य की समीक्षा करने एवं बीआरसीसी को एजेंसियों से समन्वय बनाकर निर्माण कार्यों का अपडेट देने का निर्देश दिया। आज के बैठक में सभी एजेंसियों के विभागीय अधिकारी, जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला मिशन समन्वयक एवं बीआरसीसी उपस्थित थे।

वीं जुनियर नेशनल वॉलीबाल चैम्पियनशिप हेतु नेशनल टीम में सूरजपुर से 2 कोच का चयन

सूरजपुर ब्यूरो (दैनिक विश्व परिवार) पश्चिम बंगाल के हुगली में होने वाली 46 वीं सब जुनियर नेशनल वॉलीबाल चैम्पियनशिप का आयोजन 24 फरवरी से 01 मार्च तक आयोजित है, जिसमें छत्तीसगढ़ राज्य के बालक एवं बालिका दोनों ही वर्गों की टीम भाग ले रही है। जिसमें सहायक कोच हेतु बालक वर्ग में सूरजपुर निवासी रविन्द्र सिंह एवं बालिका वर्ग में सूरजपुर लटोरी निवासी हेमन्त कुमार का चयन किया गया है।

सूरजपुर एमेच्योर वॉलीबाल संघ जिला अध्यक्ष श्री अजय गोयल के द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर नाम रोशन करते हुये उत्तरोत्तर प्रगति की शुभकामनाएं दी गई। जिला सचिव रामश्रृंगार यादव के द्वारा खुशी जाहिर करते हुये इसे सूरजपुर जिला की बड़ी उपलब्धि बताया है। सूरजपुर एमेच्योर वॉलीबाल एसोसिएशन के अध्यक्ष श्री अजय गोयल के मार्गदर्शन में, सचिव श्री राम श्रृंगार यादव ने संघ के सदस्यों से संबाद कर जिले की सभी टीमों से लगातार संपर्क बनाने से सूरजपुर जिले को एक नई पहचान मिली है। सब जुनियर नेशनल बालक वर्ग के सहायक कोच के रूप में श्री रविन्द्र सिंह एवं बालिका वर्ग के सहायक कोच श्री हेमन्त कुमार राजवाड़े ने कोलकाता (हुबली) में अपने दायित्वों का निर्वहन कर सूरजपुर वॉलीबाल संघ को गौरवान्वित कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ स्टेट वॉलीबाल एसोसिएशन के अध्यक्ष श्री महेश गांगड़ा, उपाध्यक्ष मोहम्मद अकरम खान एवं सचिव श्री हेम प्रकाश नायक ने सूरजपुर एमेच्योर वॉलीबाल एसोसिएशन को यह दायित्व मिला संघ के प्रति आभार व्यक्त करता है।

सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स ने आज अपने गैलेक्सी इकोसिस्टम में गैलेक्सी एआई का विस्तार किया

नई दिल्ली। सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स ने आज अपने गैलेक्सी इकोसिस्टम में गैलेक्सी एआई का विस्तार करते हुए 'मल्टी-एजेंट इकोसिस्टम' को और मजबूत करने की घोषणा की है। कंपनी का उद्देश्य यूजर्स को अधिक विकल्प, और बेहतर नियंत्रण देना है, ताकि वे अपने दैनिक कार्य कम मेहनत और अधिक स्वाभाविक तरीके से पूरे कर सकें। कंपनी के अनुसार, अब लोग अलग-अलग कार्यों के लिए कई तरह के एआई एजेंट्स का उपयोग कर रहे हैं। हालांकि आंकड़ों के मुताबिक, 10 में से लगभग 8 यूजर्स दो या उससे अधिक एआई एजेंट्स पर निर्भर हैं। इसी बदलाव को देखते हुए, सैमसंग गैलेक्सी एआई को इस तरह विकसित कर रहा है कि यूजर अपनी पसंद और जरूरत के हिसाब से अलग-अलग इंटीग्रेटेड एआई अनुभवों को चुन सकें। गैलेक्सी एआई को ऑपरेटिंग सिस्टम के स्तर पर गहराई से जोड़ा गया है। यह केवल किसी एक ऐप तक सीमित रहने के बजाय पूरे डिवाइस के सिस्टम लेवल पर काम करता है।

संपादकीय

सांप्रदायिक भावनाओं के कारण तनाव.....

राजनेताओं को स्वार्थ से उठ कर समस्या पर विचार करना चाहिए। समाज में सांप्रदायिक भावनाओं के कारण व्यक्तिगत रिश्ते तनाव में आ रहे हों, तब थोपी गई एकता कारगर नहीं हो सकती। जहरूत पहले सामाजिक दुराव खत्म करने की है। पिछले महीने मणिपुर चूराचंदपुर में 31 वर्षीय मयंगलम्बम सिंह का अपहरण कर हत्या कर दी गई थी, जब वे अपनी मंगेतर से मिलने गए थे। मंगेतर कुकी-जो समुदाय की थी। उस हृदय-विदारक घटनाक्रम में इकट्ठी भीड़ ने युवती को वहां से जाने दिया। उसके बाद मयंगलम्बम सिंह को मार डाला गया। हत्यारों ने दया की भीख मांगते उस व्यक्ति का वीडियो बनाया और उसे सोशल मीडिया पर प्रचारित किया। इस घटना से जाहिर हुआ था कि पौने तीन साल से जारी हिंसा ने मैतेई और कुकी समुदायों में किस हद तक दुराव पैदा किया है। उस घटना के बाद मीडिया में आई रिपोर्टों से संकेत मिला है कि सांप्रदायिक नफरत का ये जहर किस हद तक फैला चुका है। असर इतना घातक है कि अब विवाहित मैतेई और कुकी दंपती अपने को मुसीबत में पा रहे हैं। ऐसे कई सामने आए मामले हैं, जिनमें ऐसे दंपतियों पर तलाक लेने का दबाव उनके समुदाय के लोगों ने बनाया है। उनमें कई दंपतियों की कई संतानें भी हैं। कुछ मामले तो ऐसे हैं, जिनमें पति-पत्नी हिंसा भड़कने के बाद से अलग रहने को मजबूर हैं। हैरतअंगेज है कि राजनीतिक दलों को समाज में उभरी ऐसी विभाजक प्रवृत्तियों की फिक्र नहीं है। इन हालात को नजरअंदाज करते हुए भारतीय जनता पार्टी ने इस महीने मणिपुर में नई सरकार बनाई। उसके बाद से राज्य में हिंसा का नया दौर आया हुआ है। चूराचंदपुर, उखरल और अन्य कुकी बहुल इलाकों में आगजनी, पथराव, पुलिस से झड़प आदि जैसी अनेक घटनाएं हुई हैं। कुकी-जो समुदाय के लोग अपनी बहुलता वाले इलाकों को केंद्र शासित प्रदेश बनाने की मांग कर रहे हैं। यानी वे मणिपुर का हिस्सा नहीं रहना चाहते, जिसमें मैतेई बहुसंख्यक हैं। राजनेताओं को थोड़े समय के लिए स्वार्थ से उठ कर इस समस्या पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। उन्हें समझना चाहिए कि जब समाज में सांप्रदायिक भावनाओं के कारण व्यक्तिगत रिश्ते तनाव में आ गए हों, तब ऊपर से थोपी गई राजनीतिक एकता कारगर नहीं हो सकती। अतः जहरूत पहले सामाजिक दुराव खत्म करने की है। इसे जितना नजरअंदाज किया जाएगा, स्थिरतायं उतनी ही विकट होती जाएंगी।

आलेख

यूट्यूब से कमाई का बुलबुला फूट रहा

हरिशंकर व्यास

भारत में तीन दशक पहले डिजिटल क्रांति आई तो भारत कंप्यूटर और इंटरनेट का दुनिया का सबसे बड़ा बाजार बना। वैसे ही डेढ़ दशक पहले सोशल मीडिया का क्रांति हुई तो भारत उसका भी सबसे बड़ा बाजार बना। भारत में अभी फेसबुक, यूट्यूब, गूगल आदि के सबसे ज्यादा उपयोगकर्ता हैं। इसी तरह दो साल पहले जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई की क्रांति हुई उसका भी सबसे बड़ा बाजार भारत बन गया है। भारत में ओपन एआई का इस्तेमाल करने वाले सबसे ज्यादा लोग हैं। जिस तरह से भारत आईटी क्रांति और सोशल मीडिया क्रांति का बाजार बना है उसी तरह एआई क्रांति का भी बाजार बना है। लेकिन अब इस बाजार के डायनेमिक्स बदल रहे हैं। अमेरिका की एआई कंपनियों ने मार्केटिंग की दिशा में अगला कदम बढ़ा दिया है। खबर है कि अब उनके एआई प्लेटफॉर्मस का इस्तेमाल मुफ्त नहीं होगा। पहले चरण में इसमें विज्ञापन इंट्रोड्यूस किए जा रहे हैं। एआई का कोई भी प्लेटफॉर्म खोलने पर विज्ञापन चलेगा। अगर किसी को विज्ञापन मुक्त सेवा लेनी है तो उसे सब्सक्रिप्शन लेना होगा। मार्केटिंग का एक तरीका सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मस द्वारा पहले से आजमाया जाने लगा है। प्रीमियम सर्विस के लिए पैसे देने होते हैं और मुफ्त सर्विस में विज्ञापन चलते हैं। इस विज्ञापन से अरबों डॉलर की कमाई होती है और वह पूरा पैसे अमेरिका जाता है। सोचें, विज्ञापन भारत के उत्पादों का होता है और उनके खरीदार भी भारत के लोग होते हैं। लेकिन उसका विज्ञापन करने वाला प्लेटफॉर्म विदेशी है। पहले विज्ञापन का प्लेटफॉर्म अखबार, पत्रिकाओं और टेलीविजन चैनलों का होता था। बाद में इसमें डिजिटल प्लेटफॉर्मस शामिल हुए। धीरे धीरे उन्होंने बाजार पर कब्जा करना शुरू किया। सरकारों ने डिजिटल प्लेटफॉर्मस पर विज्ञापन के नए नियम बनाए। आज विज्ञापन का सबसे ज्यादा हिस्सा डिजिटल प्लेटफॉर्मस को जाता है। उसमें गूगल, यूट्यूब, फेसबुक, एक्स, इंस्टाग्राम आदि की सबसे ज्यादा हिस्सेदारी है। ऐसा नहीं है कि इसका लाभ सिर्फ अमेरिकी कंपनियों ने उठाया। उन्होंने भारत के सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को कमाई का माध्यम भी उपलब्ध कराया। भारत में रील बनाना और डिजिटल कंटेंट बना कर कमाई करना एक वैकल्पिक रोजगार बना। ऐसा रोजगार, जिसमें सरकारों की कोई भूमिका नहीं थी लेकिन पिछले ही साल बिहार में चुनाव प्रचार के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि उन्होंने डाटा इतना सस्ता कर दिया कि लाखों लोग डिजिटल कंटेंट बना कर कमाई कर रहे हैं। उन्होंने रीलबाजी को एक रोजगार बताया। इतना ही नहीं इस साल जब मोदी की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आम बजट पेश किया तो उसमें 15 हजार कंटेंट क्रिएशन लैब्स बनाने का प्रावधान किया। सोचें, दुनिया के सभ्य और विकसित देश इंटेलेक्टुअल प्रोडर्प्टी बनाने के लिए साइंस और टेक्नोलॉजी के लैब्स बना रहे हैं वही भारत में कंटेंट क्रिएशन के लैब बनने हैं। परंतु इस रोजगार की राह भी अब मुश्किल हो गई है। तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने दर्शकों और पाठकों तक रीच घटाई है। साथ ही मोनेटाइजेशन को कम किया है। फेसबुक जैसे प्लेटफॉर्म पर तो पहले भी कम पैसे मिलते थे लेकिन यूट्यूब वीडियोज से लोगों को अच्छी खासी कमाई होती थी। पहले तो इनकी पैरेंट कंपनी मेटा ने वीडियो को लंबाई और गुणवत्ता के आधार पर भुगतान के नए नियम बनाए। इसमें छोटे यानी शॉर्ट वीडियोज और रील्स के लिए भुगतान काफी कम कर दिया। लंबे वीडियो पर अगर दर्शक ज्यादा देर टिकता था तो उसमें ज्यादा भुगतान के नियम बने। इस तरह 30 सेकेंड, तीन मिनट या उससे ज्यादा, 10 मिनट या उससे ज्यादा और 30 मिनट या उससे ज्यादा की अवधि वाले वीडियो की श्रेणियां बनाई गईं। पहले ये कंपनियां अनापशाना पैसे देती थीं। लेकिन बाद में 10 मिनट का वीडियो अगर 10 हजार लोग देखते हैं तो एक डॉलर का भुगतान होने लगा। अब इसे और कम कर दिया गया है। एक बहुत ही चर्चित और वस्तुनिष्ठ खबरें दिखाने वाले सोशल मीडिया जर्नलिस्ट का कहना है कि उनके लंबे वीडियो पर पांच लाख व्यूज के बावजूद तीन हजार रुपए मिल रहे हैं।

पाणिनि से एआई स्टैक तक.....दिल्ली का एआई गौरव और राष्ट्रीय क्षमता का लक्ष्य

हरदीप एस पुरी



जब पाणिनि ने बोली जाने वाली भाषा की अव्यवस्था को एक संक्षिप्त, गणनीय व्याकरण में परिवर्तित किया, तो उन्होंने एक बात साबित की, जो आज भी प्रासंगिक है: बुद्धिमत्ता सबसे शक्तिशाली तब होती है, जब इसे संरचना के रूप में व्यवस्थित किया जाता है। नार्लंदा इस सहज प्रवृत्ति को संस्थाओं तक ले गया और बहस करने, संरक्षित करने और ज्ञान को सीमाओं के पार प्रसार करने के तरीके विकसित किए। भारत एआई इम्पैक्ट समिट 2026 की मेजबानी करने का भारत का निर्णय उसी सभ्यतागत भावना से प्रेरित है, क्योंकि तकनीक में अगली छलांग उन प्रणालियों के बारे में है, जो सीख सकती हैं, तर्क कर सकती हैं और बड़े पैमाने पर कार्य कर सकती हैं और दुनिया ऐसे भविष्य के बारे में सोच नहीं सकती, जिसमें केवल कुछ देश यह तय करें कि ये प्रणालियाँ कैसे बनाई जाएंगी। पिछले सप्ताह भारत मण्डपम में आयोजित यह शिखर सम्मेलन, एक वैश्विक दक्षिण राष्ट्र द्वारा आयोजित पहला वैश्विक एआई शिखर सम्मेलन था और किसी भी पूर्व आयोजन में इस स्तर की भागीदारी नहीं देखी गयी: 20 से अधिक राष्ट्राध्यक्ष, 60 मंत्री, 100 से अधिक देशों के 500 से अधिक एआई दिग्गज और विषय-आधारित दस स्पेलियरों में 300 प्रदर्शक। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में, भारत अपनी स्वयं की एक संगठनात्मक सोच प्रस्तुत कर रहा है: डेटा पर संप्रभुता, डिजाइन के अनुसर समावेश और स्वाभाविक जवाबदेही। देश वैश्विक पूंजी को इन शर्तों पर यहाँ निवेश करने के लिए आमंत्रित कर रहा है। प्रधानमंत्री के एम.ए.एन.ए.वी विजन में इस विचार की स्पष्ट अभिव्यक्ति हुई है: नैतिक पाबंदी, जवाबदेह शासन, डेटा पर संप्रभुता, ताकि ज्ञान के कच्चा माल का उस रूप में निष्कर्षण न किया जाए जैसे कभी वस्तुओं

का किया जाता था; व्यापक पहुंच, ताकि लाभ मध्य प्रदेश के किसान तक उतने ही निश्चित रूप से पहुंचे, जितना बेंगलुरु के इंजीनियर तक और कानूनी वैधता, ताकि हर प्रत्येक प्रणाली लोकतांत्रिक निरीक्षण के प्रति जवाबदेह बनी रहे। उनकी अवधारणा एआई को खुला आकाश देने की है, जबकि नियंत्रण मानव हाथों में रखा जाना चाहिए। यह अवधारणा एक ऐसी रेखा खींचती है, जिसे कई उन्नत अर्थव्यवस्थाएं खींचने में हिचकिया रही हैं। अब इन सिद्धांतों का बहुपक्षीय महत्व है, जो शिखर सम्मेलन में अपनाई गई दिल्ली घोषणा के माध्यम से सामने आया, और इसे पहले से ही वैश्विक दक्षिण से आने वाली पहली प्रमुख एआई शासन रूपरेखा कहा जा रहा है। इस घोषणा की दृष्टि विकास-उन्मुख है, जिसका केंद्र तकनीकी-कानूनी दृष्टिकोण है और जो कठोर अनुपालन की तुलना में लचीली पाबंदियों को प्राथमिकता देता है। यह वैश्विक सहयोग को तीन स्तंभों पर व्यवस्थित करता है: लोग, पृथ्वी और प्रगति। भारतजनेन जैसा जनसंख्या के पैमाने पर आधारित समाधान, जो 22 भारतीय भाषाओं का समर्थन करता है और उस वास्तविकता को संजोहित करता है कि दुनिया का अधिकांश भाग अंग्रेजी में काम नहीं करता। भारत के अपने सब्सिडी वाले जीपीयू एक्ससेस (265 प्रति घंटा) पर आधारित एक प्रस्तावित वैश्विक कंप्यूट बैंक प्रवेश बाधाओं को हर जगह कम करता है। घोषणा में डेटा संप्रभुता पर जोर दिया गया है, जो सीधे एआई निष्कर्षणवाद को चुनौती देता है: एक पैटर्न, जिसमें विकासशील देशों से डेटा संग्रहित किया जाता है ताकि मॉडल को प्रशिक्षित किया जा सके। बाद में देशों को इसी मॉडल के लिए भुगतान करना पड़ता है। पिछले दशक के कार्यान्वयन ने इस रूपरेखा को विश्वसनीयता दी है, क्योंकि यह सरकार एआई तक किसी श्वेत पत्र के माध्यम से नहीं, बल्कि किसी भी लोकतांत्रिक देश द्वारा शुरू किये गये सबसे महत्वाकांक्षी डिजिटल सार्वजनिक अवसरदाता कार्यक्रम के जरिये पहुंची है। यूपीआई ने 2025 में 228 बिलियन से अधिक लेन-देन संसाधित किए, जिनका मूल्य लगभग 3.4 ट्रिलियन डॉलर था, जो दुनिया के वास्तविक समय पर कुल डिजिटल भुगतान का लगभग

आधा है और यह वैश्विक स्तर पर वीसा द्वारा संसाधित किये गये कुल लेन-देन से भी अधिक है। जेएएम त्रय ने 2015 से अब तक 73.48 लाख करोड़ से अधिक की कल्याण बचत प्रदान की है। किसी अन्य देश ने एक ही नीतिगत व्यवस्था के तहत पहचान, भुगतान और पात्रता-अधिकार के वितरण का निर्माण इस स्तर पर नहीं किया है और यही वह आधारशिला है, जिस पर भारत का एआई खाड़ा है। यदि डिजिटल सार्वजनिक अवसरदाता का लक्ष्य हर नागरिक को देश से जोड़ना था, तो एआई अवसरदाता का लक्ष्य हर नागरिक को क्षमता से जोड़ना है और यहाँ आंकड़े एक चॉकाने वाला अंतर दिखाते हैं: भारत दुनिया के लगभग 20 प्रतिशत डेटा का उत्पादन करता है, लेकिन यहाँ वैश्विक डेटा-केंद्र क्षमता का केवल लगभग 3 प्रतिशत मौजूद है। अब इस अंतर को उसी इरादे के साथ पाटा जा रहा है, जिसने यूपीआई का निर्माण किया था: तेज, बड़े पैमाने पर और संप्रभु डिजाइन के साथ। विचार करें कि भारत मंडपम में एक ही सप्ताह में क्या घोषणाएँ की गईं। माइक्रोसॉफ्ट: 2030 तक वैश्विक दक्षिण के लिए 50 बिलियन डॉलर, जिसमें से पहले ही 17.5 बिलियन डॉलर की भारत के लिए प्रतिबद्धता व्यक्त की गयी है। गूगल: अमेरिका-भारत संपर्क पहल, जो पांच वर्षों में 15 बिलियन डॉलर से संचालित होगी। अमेज़न वेब सर्विसेज: महाराष्ट्र में 8.3 बिलियन डॉलर। अदानी समूह: 2035 तक नवीकरणीय ऊर्जा-संचालित एआई डेटा केंद्रों के लिए 100 बिलियन डॉलर। योटा डेटा सर्विसेज: एनवीडिया के ब्लैकवेल अल्ट्रा चिपस का उपयोग करके एशिया के सबसे बड़े एआई कंप्यूटिंग हब में से एक के लिए 2 बिलियन डॉलर से अधिक। लार्सन एंड टुब्रो: एनवीडिया के साथ भारत की सबसे बड़ी गीगावाट-स्केल एआई फैक्ट्री बनाने के लिए प्रस्तावित परियोजना। इंडियाएआई मिशन का राष्ट्रीय कंप्यूट क्लस्टर 38,000 जीपीयू पार कर चुका है और इसे 58,000 तक बढ़ाया जा रहा है, जो स्टार्टअप के लिए वैश्विक लागत के लगभग एक तिहाई पर उपलब्ध है। अगले दो वर्षों में एआई अवसरदाता में 200 अरब डॉलर के निवेश का सरकार का लक्ष्य महज आकांक्षा नहीं है; घोषित प्रतिबद्धताएँ इसे हासिल करने के दायरे

में लाती हैं। केंद्रीय बजट 2026-27 का उद्देश्य इस निवेश को दीर्घकालिक संरचनात्मक लाभ में बदलने का है, जो उन विदेशी कंपनियों के लिए टेक्स होलीडे का 2047 तक विस्तार करता है, जो वैश्विक क्लाउड सेवाओं के लिए भारतीय डेटा सेंटर का उपयोग करती हैं तथा एआई और उच्चतम निर्माण स्टार्टअप के लिए 1.1 अरब डॉलर के वेंचर कैपिटल फंड का वचन देती हैं। राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन, जिसका परियोजना 34,000 करोड़ रुपये से अधिक का है, लिथियम, कॉबाल्ट और दुर्लभ पृथ्वी धातुओं को सुरक्षित करता है, जिन पर एआई और सेमीकंडक्टर का निर्माण निर्भर होता है। हालाँकि यह सब तब तक मायने नहीं रखता, जब तक यह लोगों तक नहीं पहुँचता। शिखर सम्मेलन के पहले दिन, 2.5 लाख से अधिक छात्रों ने नवाचार के लिए जिम्मेदार एआई का उपयोग करने की शपथ ली, यह संख्या गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स की मान्यता के लिए प्रस्तुत की गई है। तीस डेटा और एआई लैब्स स्तर 2 और स्तर 3 के शहरों में काम कर रहे हैं, जो 570-लैब नेटवर्क की योजना का पहला प्रयास है, जबकि एआईकोश 7,500 से अधिक डेटासेट और 273 मॉडलों को साझा सार्वजनिक अवसरदाता के रूप में पेश करता है। जब यह सरकार सत्ता में आई थी, तब भारत में 16 आईआईटी थे; आज 23 हैं। ओपनएआई के सीईओ ने बताया कि भारत चैटजीपीटी का दूसरा सबसे बड़ा बाजार है, जिसके 100 मिलियन साप्ताहिक सक्रिय उपयोगकर्ता हैं। खपत यहाँ है, और उत्पादन क्षमता रफ़्तार पकड़ बना रही है: शिखर सम्मेलन में तीन संप्रभु एआई मॉडल पेश किए गए, जिनमें सर्वम एआई का 105 बिलियन डॉलर व्यापक भाषा मॉडल शामिल है, जिसे पूरी तरह भारतीय कंप्यूटिंग और भारतजनेन का परम2 पर प्रशिक्षित किया गया है, एक 17-बिलियन-पैरामीटर बहुभाषी मॉडल, जो सभी 22 अनुसूचित भाषाओं का समर्थन करता है। ये विदेशी मॉडलों के अनुकूल किये गये संस्करण नहीं हैं; इन्हें संप्रभु अवसरदाता पर शुरूआत से बनाया गया है। यह भी जानकारी देने योग्य है कि साझेदारी की संरचना अब कैसे तैयार की जा रही है, क्योंकि अब यह विदेशी तकनीक के लाइसेंस के बारे में नहीं है।

देशी कंपनियों के सामने हार्ले डेविडसन की चुनौती

अजीत द्विवेदी

भारत और अमेरिका के बीच दोषपक्षी व्यापार वार्ता चलती रहेगी लेकिन उससे पहले अंतरिम समझौते की घोषणा हो गई है। जिस दिन घोषणा हुई यानी समझौते का फ्रेमवर्क और साझा बयान जारी हुआ उसके अगले दिन, आठ फरवरी को पता नहीं अमेरिका के अखबारों में किसी भारतीय उत्पाद का विज्ञापन छपा या नहीं, लेकिन भारत की राजधानी दिल्ली में सभी बड़े अखबारों में पहले पन्ने पर पूरे पेज पर अमेरिकी मोटरसाइकिल हार्ले डेविडसन का विज्ञापन छपा। 125 सीसी की हार्ले डेविडसन मोटरसाइकिल की कीमत तीन लाख रुपए से कम बताई गई। ध्यान रहे यह कोई सामान्य मोटरसाइकिल नहीं है। यह अमेरिकी औद्योगिक उत्पादन शृंखला का प्रतीक उत्पाद है। पहली बार राष्ट्रपति रहते डोनाल्ड ट्रंप इसी बाइक पर लगने वाले सी फीसदी से ज्यादा टैरिफ को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से नाराज हुए थे। उन्होंने भारत को टैरिफ किंग कहा था। बाद में भारत सरकार ने इस पर लगने वाला शुल्क कम किया। अब खबर है कि नए समझौते के तहत इस पर जीरो टैरिफ लगेगा। भारत में मोटरसाइकिल का बाजार बहुत बड़ा है और अब देशी कंपनियों के सामने हार्ले डेविडसन की चुनौती है। बहरहाल, अमेरिका के साथ होने वाले सौदे को लेकर बहुत सी बातें कही और लिखी जा चुकी हैं। जैसे पहले भारतीय उत्पादों पर तीन फीसदी टैरिफ लगता था अब 18 फीसदी लगेगा और भारत में अमेरिकी उत्पादों पर

औसतन 15 फीसदी टैरिफ लगता था, जिसको शून्य किए जाने की खबर है। इसी तरह भारत ने रूस से तेल खरीदना कम कर दिया है और अमेरिका से खरीद बढ़ा दी है। ऐसे ही भारत अब वेनेजुएला से तेल खरीदना शुरू करेगा। यह तेल भारत को महंगा पड़ेगा। फ्रेमवर्क का झुप्ट सामने आने और रूस से तेल खरीद की वजह से भारत पर लगाए गए 25 फीसदी अतिरिक्त टैरिफ को वापस लेने के राष्ट्रपति ट्रंप के कार्यकारी आदेश की प्रति सामने आने के बाद कुछ नई और दिलचस्प चीजें पता चली हैं। ट्रंप के कार्यकारी आदेश में लिखा हुआ है कि अगर भारत ने फिर रूस से तेल खरीदना शुरू किया तो उसके ऊपर 25 फीसदी टैरिफ लगाया जा सकता है। सोचें, किसी संप्रभु राष्ट्र के लिए क्या कोई दूसरा देश इस तरह के आदेश और धमकी जारी कर सकता है? ट्रंप ने भारत के लिए जारी किया लेकिन सब अपनी सुविधा के हिसाब से उनकी अनदेखी कर रहे हैं। ऐसे ही फ्रेमवर्क में एक दिलचस्प बात यह है कि भारत अगले पांच साल में अमेरिका से पांच सी अरब डॉलर के सामान खरीदेगा। यानी हर साल भारत को एक सौ अरब डॉलर के सामान खरीदने हैं। सवाल है कि भारत क्या खरीदेगा? अभी अमेरिका से भारत की औसत सालाना खरीद 40 अरब डॉलर की है। इसको दोगुने से ज्यादा बढ़ाना है। भारत अमेरिका से ऐसा क्या खरीदना शुरू करेगा कि उसका आयात दोगुने से ज्यादा बढ़ कर सी अरब डॉलर यानी करीब नौ लाख करोड़ रुपए का हो जाएगा? यह सही है कि भारत ने तेल खरीद बढ़ा दी है। तेल व गैस की खरीद

थोड़ी और बढ़ाई जा सकती है। कुछ विमान व विमानों के कल पुर्जों की खरीद बढ़ जाएगी लेकिन क्या इससे भारत का आयात दोगुना हो जाएगा? कम से कम पहले साल में तो नहीं होने वाला है। भारत दुनिया के दूसरे देशों से सस्ती और जरूरत की चीजें छोड़ कर अमेरिका से ज्यादा और गैरजरूरी चीजों की खरीद करे तब तो बात अलग है। अन्यथा ऐसे हर साल नौ लाख करोड़ रुपए का सामान खरीदना मुश्किल होगा। अगर भारत ने समझौते की इस शर्त को पूरा नहीं किया तो क्या होगा? सबको पता है कि राष्ट्रपति ट्रंप ने अपने सबसे करीबी सहयोगियों में से एक दक्षिण कोरिया के साथ क्या किया? उन्होंने दक्षिण कोरिया से समझौता किया और एक दिन अचानक कहा कि वह समझौते की शर्तों को ठीक से लागू नहीं कर रहा है इसलिए उसके ऊपर 25 फीसदी टैरिफ लगाया जाता है। भारत के सामने भी यह खतरा बनीका। ध्यान रहे अभी तक भारत और अमेरिका के बीच व्यापार में संतुलन भारत के पक्ष में था। अमेरिका से भारत अभी करीब चार लाख करोड़ रुपए का सामान खरीदता है और उसे सात लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का सामान बेचता है। दुनिया के ज्यादातर देशों के साथ अमेरिका का व्यापार संतुलन ऐसा ही था। तभी राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि अब तक अमेरिका सभी देशों के साथ व्यापार में घाटा उठाता रहा है, अब वे इसे बदलेंगे। यानी अब अमेरिका मुनाफा कमाएगा। भारत के साथ व्यापार में भी ऐसा ही होगा। अब व्यापार संतुलन अमेरिका के पक्ष में होगा। अगर भारत चाहता है कि ऐसा न हो तो वह अमेरिका से नौ

लाख करोड़ रुपए का सामान खरीदेगा और उसे इससे ज्यादा का सामान बेचना होगा। सोचें, अभी भारत सात लाख करोड़ रुपए से कुछ ज्यादा का सामान बेचता है अब अचानक तीन या चार लाख करोड़ रुपए का कौन सा सामान बेचने लगेगा कि व्यापार संतुलन भारत के पक्ष में झुके? यह भी ध्यान रखने की जरूरत है कि यूरोपीय संघ के साथ भी भारत ने मुक्त व्यापार संधि की है। ब्रिटेन और न्यूजीलैंड के साथ भी संधि हुई है। इन देशों को भी सामान बेचना है। इसे एक अवसर माना जा सकता है। लेकिन क्या अवसर का लाभ उठाने के लिए भारत तैयार है? सौदे में एक और दिलचस्प बात यह है कि वाणिज्य मंत्री ने उन वस्तुओं की सूची गिनाई, जिनका निर्यात भारत करेगा। उसमें सेब और एवाकाडो भी हैं। सोचें, भारत में अपने इस्तेमाल का एवाकाडो तंजाविया, पेरू, चिली, ऑस्ट्रेलिया आदि देशों से आता है तो भारत कहां से एवाकाडो अमेरिका को निर्यात करेगा। इसी तरह भारत में सेब की अपनी जरूरत अमेरिका से लेकर न्यूजीलैंड और चीन के सेब से पूरी होती है। बहरहाल, भारत को एक तरफ अनाज, फल आदि का उत्पादन बढ़ाना होगा, उन्हें पेरिस्टसाइड से मुक्त करना होगा और अमेरिका व यूरोपीय स्टैंडर्ड का करना होगा। उसके साथ ही अपना बुनियादी ढांचा भी मजबूत करना होगा। सरकार कह रही है कि उसने किसानों के हितों से कोई समझौता नहीं किया है। लेकिन अभी समझौते का अंतिम मसौदा सामने आना बाकी है। सरकार ने सोयाबीन तेल पर से टैरिफ हटा दिया है।

अभिभावकीय चेतना से निखरेगा बचपन

अनुज आचार्य

अंततः, बच्चों की रुचि को पहचानना और उसी दिशा में उन्हें प्रोत्साहित करना माता-पिता का सबसे बड़ा योगदान हो सकता है। किसी विषय में कमजोरी को लेकर अनावश्यक दबाव बनाने के बजाय, उसकी प्रतिभा को पहचानना और उसे संवारना ही सच्ची अभिभावकीय भूमिका है आज के तेज रफ्तार और प्रतिस्पर्धात्मक युग में बच्चों का भविष्य केवल उनकी पढ़ाई तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि उनके संपूर्ण व्यक्तित्व के निर्माण का प्रश्न बन गया है। इस पूरी निर्माण-प्रक्रिया में माता-पिता की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण, सबसे निर्णायक और सबसे संवेदनशील हो चुकी है। सच कहा जाए तो बच्चों का भविष्य किसी विद्यालय की इमारत में नहीं, बल्कि माता-पिता के व्यवहार, सोच और संस्कारों की गोद में आकार लेता है। मां-बाप बनना और बच्चे पैदा करना एक प्राकृतिक प्रक्रिया है, परंतु बच्चों के प्रति जिम्मेदारियों को निभाना एक बड़ा जीवन-दायित्व है। यह कोई एक दिन या एक चरण का कार्य नहीं, बल्कि आजीवन चलने वाली साधना है। बच्चे केवल हमारे नाम को आगे बढ़ाने का माध्यम नहीं, बल्कि ईश्वर द्वारा सौंपी गई अमानत हैं, जिनकी

सही परवरिश हमारा कर्तव्य भी है और परीक्षा भी। बच्चों की परवरिश का पहला आधार है, स्वस्थ परेल्ड वातावरण। घर का माहौल शांत, प्रेमपूर्ण और सुरक्षित होगा तो बच्चे स्वतः ही मानसिक रूप से सुदृढ़ बनेंगे। बच्चों को मानसिक तनाव और पारिवारिक विवाद से बचाने हेतु घर में प्रेम, खुला संवाद और स्थिर वातावरण रखें। दिनचर्या संतुलित बनाएं, खेल-व्यायाम एवं अन्य रुचियों के परिमार्जन हेतु प्रोत्साहित करें, उनके सामने झगड़े से बचें, सुरक्षा का भरोसा दें। इसके साथ ही उचित खानपान और पौष्टिक आहार की व्यवस्था करना माता-पिता की प्राथमिक जिम्मेदारी है। बच्चों को जंक फूड से दूर रखें। संतुलित आहार, नियमित दिनचर्या और पर्याप्त नींद बच्चों के समग्र विकास की नींव हैं। शारीरिक और मानसिक विकास के बाद आता है बौद्धिक विकास। इसके लिए केवल किताबें ही पर्याप्त नहीं होतीं, बल्कि घर में सकारात्मक चर्चा और स्वस्थ बहस का वातावरण ही उनका ही जरूरी है। जब बच्चे सवाल पूछते हैं, तर्क करते हैं या किसी विषय पर अपनी राय रखते हैं, तो उन्हें डांटने या चुप कराने के बजाय सुनना चाहिए। यही प्रक्रिया उनके सोचने-समझने की क्षमता को विकसित करती है और उन्हें जिज्ञासु, आत्मनिर्भर और रचनात्मक बनाती



है। जब बच्चों को यह एहसास होता है कि उनकी भावनाओं की कद्र हो रही है, तब उनमें आत्मविश्वास पनपता है और वे खुलकर अपने मन की बात साझा करने लगते हैं। आज एकल परिवारों की बढ़ती संख्या के कारण बच्चों के पास खेलने-कूदने और संवाद के लिए साथी कम होते जा रहे हैं। ऐसे में माता-पिता की भूमिका और भी बढ़ जाती है। बच्चों को अच्छे संस्कार, नैतिक मूल्य और मर्यादा जैसी जीवन की शिक्षा देना अनिवार्य हो गया है। उनकी संगति, आवागमन और गतिविधियों पर सतर्क नजर रखना जरूरी है, ताकि वे नशे जैसी सामाजिक बुराइयों से दूर रहें। मोबाइल फोन और इंटरनेट का बढ़ता दुरुपयोग भी आज एक गंभीर चुनौती बन

चुका है। हाल ही के कुछ घटनाक्रमों और गतिविधियों में मोबाइल की लत से तनावग्रस्त तीन बहनों द्वारा की गई आत्महत्याओं के आलोक में हिमाचल में 01 मार्च 2026 से सकारात्मक रूप पर प्रतिबद्ध लगाने की घोषणा जैसे कदम इस खतरे की ओर स्पष्ट संकेत देते हैं। बच्चों में दया, करुणा, सहयोग, सम्मान और राष्ट्रभक्ति जैसे गुणों का विकास केवल भाषणों से नहीं, बल्कि माता-पिता के आचरण से होता है। बच्चे वही सीखते हैं जो वे अपने घर में देखते हैं। यदि घर में बुजुर्गों का सम्मान होता है, संवाद की संस्कृति होती है और दूसरों के प्रति संवेदनशीलता दिखाई जाती है, तो वही संस्कार बच्चों में स्वतः उतरते हैं। यदि

बच्चा पढ़ाई या किसी विशेष विषय में अपेक्षित सफलता नहीं पा रहा है, तो घबराने या उसे दोष देने की बजाय धैर्य रखना चाहिए। हर बच्चा अलग होता है, उसकी क्षमता और गति भी अलग होती है। ऐसे समय में माता-पिता का साथ, प्रोत्साहन और विश्वास ही बच्चे का सबसे बड़ा सहारा बनता है। 'तुम कर सकते हो' का भाव, यानी 'कैन डू' की भावना, बच्चों के भीतर आत्मविश्वास का बीज बोती है। मां बाप को चाहिए कि वे अपने बच्चों को संचर्प करना, समस्याओं का सामना करना सिखाएं। बड़े-बुजुर्गों का आदर करना भारतीय संस्कृति की आत्मा है। यह संस्कार यदि बचपन में बच्चों को मिल जाए, तो आगे चलकर यही उनके चरित्र की पहचान बनता है। साथ ही बच्चों के साथ समय बिताना, उनसे खुलकर बात करना, उन्हें धर्मशूलों की ओर संस्कृतिक स्थलों से जोड़ना भी उनके नैतिक विकास में सहायक होता है। आज हर माता-पिता यह चाहते हैं कि उनके बच्चे ऊंचे पदों पर पहुँचें, सम्मानजनक जीवन जिएं और आर्थिक रूप से सशक्त बनें। इसके लिए माता-पिता को भी त्याग करना पड़ता है, अपने समय, अपने आराम और कई-बार अपनी इच्छाओं का। बच्चों की स्कूल-प्रतिष्ठान पर नजर रखना, शिक्षकों से संवाद बनाए रखना।



संक्षिप्त समाचार

प्रोजेक्ट्स टुडे ने भारत के परियोजना इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए एआई-संचालित व्यावसायिक अवसर प्लेटफॉर्म का शुभारंभ किया

नई दिल्ली। प्रोजेक्ट्स टुडे ने भारत के परियोजना इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए एआई-संचालित व्यावसायिक अवसर प्लेटफॉर्म का अनावरण किया। यह नया प्लेटफॉर्म परियोजना जीवनचक्र संदर्भ, निविदाएं और एल1/आदेश अपडेट, तथा हितधारकों की जानकारी को एक सुविधाजनक कार्यप्रणाली में एकीकृत करता है जिससे संगठनों को सही समय पर सही परियोजनाओं से जुड़ने में मदद मिलती है।

उन्नत प्लेटफॉर्म व्यावहारिक परिणामों पर केंद्रित एआई-सक्षम विकास प्रस्तुत करता है, जिसमें वीडियो खोज, उप-परियोजना ट्रैकिंग, निविदा से आदेश तक की यात्रा की विजिबिलिटी, बोलीदाता और भागीदारी अंतर्दृष्टि, अवसर अनुमान उपकरण, विश्वसनीयता और विश्लेषण डैशबोर्ड तथा हितधारकों के साथ बेहतर संबंध मानचित्रण शामिल हैं। ये क्षमताएं यूजर्स को आवश्यकताओं के आधार पर प्रासंगिक अवसरों की तेजी से खोज को सक्षम बनाती हैं। संगठनों को चरण, दायरे और हितधारकों के बारे में स्पष्ट संदर्भ के साथ क्या हो रहा है से हमें आगे क्या करना चाहिए की ओर बढ़ने में मदद करती हैं।

25 से अधिक वर्षों के रिसेच-आधारित कवरेज के साथ प्रोजेक्ट्स टुडे 50,000 से अधिक सक्रिय परियोजनाओं पर नजर रखता है जो वर्तमान में गंभीर विचार-विमर्श, योजना, निविदा प्रक्रिया या कार्यान्वयन के चरण में हैं। यह प्लेटफॉर्म हर महीने 1,500 से अधिक नई परियोजनाओं और 10,000 से अधिक निविदाओं के साथ 1,200 से अधिक मासिक एल1/आदेश अपडेट को कैच करता है जो विभिन्न क्षेत्रों और राज्यों में निर्णय लेने में सहायक होता है। इसका उद्देश्य केवल सूचना तक पहुंच से कहीं अधिक व्यापक है। इसका मूल उद्देश्य राष्ट्र निर्माण करने वालों और इसे सक्षम बनाने वालों प्रमोटर्स, ठेकेदारों, सलाहकारों, आपूर्तिकर्ताओं, सेवा प्रदाताओं और वित्तदाताओं के बीच अवसरों का निबंध प्रवाह सुनिश्चित करना है। प्रोजेक्ट्स टुडे नई तकनीक और गहन जानकारी के साथ विकसित होता रहेगा, साथ ही एक सिद्धांत पर अडिग रहेगा: ग्राहक सर्वोपरि।

राष्ट्र सर्वोपरि। यह शुभारंभ प्रोजेक्ट्स टुडे के उस दृष्टिकोण में एक महत्वपूर्ण कदम है जिसके तहत बेहतर समयबद्ध जुड़ाव, बेहतर समन्वय और तीव्र कार्यान्वयन के माध्यम से भारत की परियोजना अर्थव्यवस्था को मजबूत किया जाएगा ताकि अवसर योजनाओं से साझेदारी तक और इरादों से परिणामों तक कुशलतापूर्वक प्रवाहित हों।

सूरज की मुस्कान: संघर्ष से स्नेहिल परिवार तक की अનોखी यात्रा

कोरवा। यह कहानी बालक सूरज (परिवर्तित नाम) के संघर्ष, धैर्य और विभाग के सतत प्रयासों की है, जिसने एक अकेले बच्चे को समाज की मुख्यधारा और एक सुरक्षित परिवार से जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

प्रारंभिक संघर्ष और संरक्षण- सूरज का जीवन चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों से होकर गुजरा। मात्र चार वर्ष की आयु में पारिवारिक स्थितियों के कारण उसे त्याग दिया गया था। पुलिस द्वारा प्रस्तुत किए जाने के बाद बाल कल्याण समिति के आदेशानुसार उसे मिशन वात्सल्य योजना के अंतर्गत सेवा भारती मातृछाया (विशेषीकृत दत्तक ग्रहण अधिकरण) में संरक्षण प्रदान किया गया।

बजट की घोषणाएं बस्तर के लोगों के लिए छलावा : जैन

घोषणापत्र के सभी प्रावधानों को लागू करे राज्य सरकार

जगदलपुर (विश्व परिवार)। पूर्व संसदीय सचिव व विधायक रेखचंद जैन ने कहा है कि बजट की घोषणाएं बस्तर के लोगों के लिए छलावा साबित हो रही हैं। बस्तर के संदर्भ में को जाने वाली घोषणाएं सालों बाद भी धरातल में नहीं उतर पाती हैं। राज्य की भाजपा सरकार को चाहिए कि वह घोषणापत्र के सभी प्रावधानों को तत्काल प्रभाव से लागू करे। श्री जैन ने कहा है कि वर्ष 2026-27 का राज्य बजट भी अलाभकारी, असंतुष्टीदायक साबित हुआ है। इसमें बस्तर के गांव, गरीब, किसान, महिलाओं, युवाओं, कर्मचारियों समेत समाज के किसी भी वर्ग के लिए कोई खास पहल नहीं की गई है। सरकार बनाने के पहले भाजपा ने जो वायदा किया था उसे पूरा करने



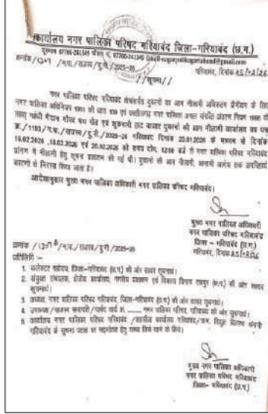
की बजाय केवल जबानी रकम खर्च करने की कवायद की गई है। ज्ञान व गति की दृष्टि के बाद संकल्प का नया जुमला वित्त मंत्री ने परोसा है, जिसे जनता जान गई है। कर्मचारियों के लिए स्पष्ट घोषणा का अभाव बस्तर जैसे क्षेत्र में सेवा देने वाले कर्मचारियों को खल रही है। एक ओर जहां बस्तर में हजारों स्कूल बंद किए गए हैं वहीं अबूझमाड़ व

जगरगुण्डा में एजुकेशन सिटी स्थापित करने का झुनझुना धमाका गया है। बस्तर के लिए की गई भाजपा की घोषणापत्र की बातें जुमला साबित हो रही हैं। बात चाहे कोंडागांव के मुका प्रोसेस प्लांट की हो या बीते सालों में गौदम में मेडिकल कॉलेज स्थापना की। जिस सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के द्वारा लोगों के मुफ्त इलाज का ढिंडीरा पीटा जा रहा था उसकी सच्चाई अब सबके सामने आ चुकी है। जैन ने कहा है कि राज्य के बजट में मनरेगा मजदूरों के लिए कोई प्रावधान न होना उनके साथ अन्याय है। यह बस्तर संभाग के लाखों परिवारों के साथ भाजपा की धोखाधड़ी भी है। कृषक उन्नति योजना में जो बातें कही गई थीं उनका पालन भी नहीं किया गया है। एक लाख रिक्त शासकीय पदों पर भर्ती का दावा स्थानीय बेरोजगारों के साथ किए गए छल के रूप में देखा जा रहा है।

शौचालय निर्माण में बड़ा घोटाला?

1.23 करोड़ की लागत, 60 लाख अग्रिम भुगतान 90 दिन की शर्त, 10 लाख भी काम नहीं!

गरियाबंद (विश्व परिवार)। जिले में स्कूलों के लिए स्वीकृत 116 शौचालयों का निर्माण कार्य सवालों के घेरे में है। 1 करोड़ 23 लाख रुपये की लागत से बनने वाले इन शौचालयों के लिए 60 लाख रुपये से अधिक की अग्रिम राशि जारी कर 90 दिनों में काम पूरा करने की शर्त रखी गई थी, लेकिन अब तक 10 प्रतिशत काम भी पूरा नहीं हुआ है। कई जगह काम अधूरा है तो कई स्थानों पर निर्माण शुरू ही नहीं हुआ। विभागों के बीच जिम्मेदारी का खेल स्कूल शिक्षा विभाग ने फरवरी 2025 में जिले के 5 ब्लॉकों के 116 शौचालयों को वित्तीय मंजूरी दी थी। प्रत्येक शौचालय की लागत 1 लाख 3 हजार रुपये तय की गई थी। बाद में कलेक्टर की स्वीकृति से यह कार्य आदिवासी विकास विभाग को सौंप दिया गया। बड़ा सवाल यह है कि जिस आदिवासी विकास विभाग के पास पिछले दो वर्षों से स्कूल जतन के करोड़ों



के भवन निर्माण कार्य अधूरे पड़े हैं, उसी विभाग को यह अतिरिक्त जिम्मेदारी क्यों दी गई? शौचालय जैसे छोटे निर्माण कार्य पंचायतों को भी दिए जा सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। गुपचुप अनुबंध, एक ही फर्म को पूरा ठेका- जुलाई माह में दुर्ग की कंचन कंस्ट्रक्शन फर्म से चुपचाप अनुबंध कर 61 लाख रुपये की अग्रिम राशि जारी कर दी गई। पूरे जिले में फैले 116 कार्य



एक ही बाहरी फर्म को सौंपे जाने से कई सवाल खड़े हो रहे हैं। जानकारों का कहना है कि इतने बड़े और बिखरे कार्य को 90 दिन में पूरा करने के लिए पर्याप्त संसाधन और बड़ी टीम की जरूरत थी। बाहरी फर्म के लिए यह संभव नहीं था, फिर भी बिना दूरदर्शिता के कार्यादेश जारी कर दिया गया। अब चर्चा है कि यह निर्णय जानबूझकर लिया गया या किसी लाभकारी समझौते का हिस्सा था। सरपंचों की उपेक्षा का आरोप- नियमों के अनुसार 20 लाख रुपये तक के निर्माण कार्य पंचायतों को दिए जा सकते हैं। बावजूद इसके नए सत्र में सरपंचों को काम नहीं के बराबर मिला

देवभोग - 20 देवभोग के 20 में से एक भी शौचालय का निर्माण शुरू नहीं हुआ है। कुल मिलाकर 60 से अधिक शौचालयों का काम प्रारंभ ही नहीं किया गया है।

सत्रों का कहना है कि जिले में फैले इस कार्य को अलग-अलग फर्मों को देने के बजाय दुर्ग की एक ही फर्म को सौंपा गया। संसाधनों की कमी और कथित प्रशासनिक संरक्षण के कारण ठेकेदार अपनी मनमानी कर रहा है।

बड़ा सवाल

60 लाख अग्रिम भुगतान के बाद भी काम क्यों नहीं? पहले से अधूरे कार्यों के बावजूद आदिवासी विकास विभाग को जिम्मेदारी क्यों? स्थानीय पंचायतों को दरकिनार क्यों किया गया? क्या यह प्रशासनिक लापरवाही है या सुनिश्चित आर्थिक खेल? जिले में बच्चों की मूलभूत सुविधा से जुड़ा यह मामला अब जनचर्चा का विषय बन चुका है। यदि समय रहते जांच और कार्रवाई नहीं हुई तो यह मुद्दा बड़े प्रशासनिक विवाद का रूप ले सकता है।

व्यावसायिक परिसर निर्माण और दुकानों की नीलामी रद्द

जनआक्रोश के आगे झुका प्रशासन, गांधी मैदान बचाने की मांग को मिली जीत

गरियाबंद (विश्व परिवार)। शहर में प्रस्तावित व्यावसायिक परिसर निर्माण और दुकानों की आम नीलामी आखिरकार बढ़ते जनविरोध के आगे निरस्त कर दी गई। नगर पालिका परिषद द्वारा गांधी मैदान, गौरव पथ रोड और शुक्रवारी हाट बाजार क्षेत्र की दुकानों की 16, 18 और 20 फरवरी 2026 को नीलामी की घोषणा की गई थी, लेकिन लगातार उठते सवालों और विरोध के बाद प्रशासन को फैसला वापस लेना पड़ा। नीलामी प्रक्रिया छत्तीसगढ़ नगर पालिका अधिनियम 1961 की धारा 109 और छत्तीसगढ़ नगर पालिका अचल संपत्ति अधिनियम 1996 के तहत प्रस्तावित थी। हालांकि नागरिकों और आवेदकों ने आरोप

लगाया कि आवश्यक राजस्व स्वीकृति और रेटा अनुमति के बिना ही निर्माण और नीलामी की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जा रही थी। स्थानीय लोगों ने यह भी आरोप लगाया कि प्रस्तावित परिसर के लिए पर्याप्त पार्किंग, सार्वजनिक शौचालय और आमजन सुविधाओं की ठोस व्यवस्था नहीं की गई थी। योजना के क्रियान्वयन से पहले मूलभूत ढांचे पर स्पष्टता नहीं होने से लोगों में असंतोष बढ़ता गया। सबसे गंभीर आपत्ति गांधी मैदान की भूमि प्रभावित होने की आशंका को लेकर सामने आई। नागरिकों का दावा है कि निर्माण कार्य से मैदान की 5 से 10 फीट भूमि प्रभावित हो सकती थी। इसे शहर की सांस्कृतिक और सामाजिक पहचान पर सीधा आघात बताया गया। नीलामी प्रक्रिया में पारदर्शिता, आरक्षण व्यवस्था और खुले बोली तंत्र को लेकर भी कई प्रश्न खड़े किए गए। विरोध कर रहे

लोगों का कहना था कि प्रक्रिया में स्पष्टता और सार्वजनिक भागीदारी का अभाव है। लगातार विरोध, खबरों और शिकायतों के बाद प्रशासन ने अंततः परियोजना और नीलामी प्रक्रिया को निरस्त करने का आदेश जारी कर दिया। इस फैसले के बाद शहर में संतोष का माहौल है। नागरिकों ने निर्णय का स्वागत करते हुए कहा कि गरियाबंद के हित और गांधी मैदान के संरक्षण को ध्यान में रखते हुए गौरव पथ मार्ग में प्रस्तावित व्यावसायिक परिसर निर्माण को रद्द करना एक सराहनीय कदम है। शहरवासियों का मानना है कि विकास योजनाएं जरूरी हैं, लेकिन जनभावनाओं, पारदर्शिता और सार्वजनिक हित को दरकिनार कर नहीं। गांधी मैदान की रक्षा को लेकर उठा आवाज ने यह साबित कर दिया कि संगठित जनशक्ति किसी भी फैसले को बदलने की ताकत रखती है।

गरियाबंद में तम्बाकू पर सख्ती की तैयारी

कोटपा एक्ट 2003 के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु पुलिस अधिकारियों की एक दिवसीय कार्यशाला संपन्न

गरियाबंद (विश्व परिवार)। राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत जिले में तम्बाकू उत्पादों के उपयोग को कम करने, रोकथाम को प्रभावी बनाने तथा कोटपा एक्ट 2003 के कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से 24 फरवरी 2026 को होटल सिटी रेजेंसी में जिला स्तरीय एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यक्रम मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के निर्देशानुसार आयोजित हुआ, जिसमें जिले के पुलिस अधिकारी एवं कर्मचारी बड़ी संख्या में शामिल हुए। कार्यशाला में मास्टर ट्रेनर के रूप में डॉ. लक्ष्मीकांत जांगड़े (डीएचओ सह

डीएनओ), डॉ. दीनीला साहू (दंत चिकित्सक), पोखराज साहू (सोशल वर्कर, एनटीसीपी) तथा उमेश सोनी (सोशल वर्कर, एनएमएचपी) सहित अन्य अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे। विशेषज्ञों ने तम्बाकू सेवन से होने वाले गंभीर स्वास्थ्य दुष्प्रभावों पर विस्तार से प्रकाश डाला और कानून के प्रभावी क्रियान्वयन में पुलिस विभाग की भूमिका को महत्वपूर्ण बताया। प्रशिक्षण के दौरान कोटपा एक्ट 2003 की धारा 4 (सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान निषेध), धारा 5 (तम्बाकू उत्पादों के विज्ञापन पर प्रतिबंध) तथा धारा 6 (अ) और (ब) (नाबालिगों को विक्री पर प्रतिबंध एवं शैक्षणिक संस्थानों के आसपास विक्री निषेध) के संबंध में विस्तृत जानकारी प्रदान की गई। अधिकारियों को मौके पर कार्रवाई, चालानी प्रक्रिया, दंड प्रावधान तथा जन-जागरूकता बढ़ाने के उपायों की भी जानकारी दी गई।

शासन की योजना से दूर हुई आर्थिक तंगी और बेटी के भविष्य की चिंता

चिरायु दल ने लौटाई मासूम रंजना की मुस्कान

जगदलपुर (विश्व परिवार)। बकावण्ड ब्लॉक के ग्राम जामगुड़ा (धनपुर) में रहने वाले महेश भारती के घर जब बेटी रंजना का जन्म हुआ, तो खुशियों के साथ-साथ एक गहरी चिंता ने भी दस्तक दी। मासूम रंजना जन्मजात 'कलेफ्ट लिप' (कटे होंठ) की समस्या से ग्रसित थी। जैसे-जैसे रंजना बड़ी हो रही थी, माता-पिता के मन में अपनी बेटी के भविष्य, उसकी पढ़ाई और समाज में उसे मिलने वाली स्वीकार्यता को लेकर डर गहराता जा रहा था। सबसे बड़ी चुनौती आर्थिक तंगी थी। एक साधारण परिवार के लिए निजी अस्पतालों में ऑपरेशन का भारी-



भरकम खर्च उठा पाना असंभव सा था, जिससे माता-पिता स्वयं को असहाय महसूस कर रहे थे। उनकी इस मायूसी के बीच उम्मीद की पहली किरण 19 जून 2025 को तब जगी, जब चिरायु दल बकावण्ड की टीम ऑगनबाड़ी केंद्र पहुँची। स्वास्थ्य परीक्षण के दौरान टीम ने रंजना की स्थिति को पहचाना और माता-पिता को ढाँढस बंधाते हुए उसे जिला प्रारंभिक हस्तक्षेप केंद्र रेफर किया। इसके बाद की राह जिला स्वास्थ्य समिति के सहयोग से आसान होती गई। 06 नवंबर 2025 को बच्चों की रायपुर के मेडिसाईन अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहाँ विशेषज्ञों ने रंजना का सफल

ऑपरेशन किया। सबसे बड़ी राहत की बात यह रही कि जाँच, ऑपरेशन और अस्पताल में रहने का समस्त खर्च शासन द्वारा वहन किया गया, जिससे महेश भारती का परिवार आर्थिक बोझ से मुक्त रहा। 13 फरवरी को जब स्वास्थ्य विभाग की टीम फॅलो-अप के लिए पहुँची, तो रंजना को पूरी तरह स्वस्थ पाया गया। बेटी के चेहरे की बनावट में आए इस सुखद बदलाव और उसकी खिलखिलाती मुस्कान ने माता-पिता के सालों पुराने डर को खत्म कर दिया है। शासन की इस कल्याणकारी योजना के प्रति आभार व्यक्त करते हुए परिजनों ने बताया कि अब वे अपनी बेटी के सुनहरे और सामान्य भविष्य को लेकर पूरी तरह आश्वस्त हैं।

कार्यालय संयुक्त संचालक एवं अधीक्षक भारत रत्न. स्व. श्री अटल बिहारी वाजपेयी स्मृति शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय संबद्ध चिकित्सालय, राजलान्दागांव (छ.ग.)

1436	23102126
॥ द्वितीय निविदा आमंत्रण सूचना ॥	
भारत रत्न. स्व. श्री अटल बिहारी वाजपेयी स्मृति शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय संबद्ध चिकित्सालय राजनांदागांव में स्थापित ऑक्सिजन प्लांट 960 एल.पी.एम. (प्लांट नंबर-1) के सी.एम.सी. (एक वर्ष) हेतु वर्ष 2025-26 में खुली निविदा आमंत्रित किया जाना है। मुहरबंद निविदायें पंजीकृत डाक / स्पीड पोस्ट / रजिस्टर्ड कोरियर के माध्यम से उल्लेखित तिथि अनुसार आमंत्रित किया जाता है, जिसका नियम / शर्तों का अवलोकन कार्यालयीन दिवस पर प्रातः 10.00 बजे से शाम 05:30 बजे तक भारत रत्न. स्व. श्री अटल बिहारी वाजपेयी स्मृति शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय संबद्ध चिकित्सालय राजनांदागांव (छ.ग.) के मुख्य भण्डार कक्ष से किया जा सकता है।	
01. निविदा प्रपत्र मूल्य	: ₹. 1000/- (वापसी अयोग्य)।
02. निविदा प्रपत्र विक्रय की प्रारंभिक तिथि	: 26/02/2026 सुबह 10.00 बजे से।
03. निविदा प्रपत्र विक्रय की अंतिम तिथि	: 12/03/2026 अपराह्न 02.00 बजे तक।
04. निविदा प्रपत्र जमा करने की अंतिम तिथि	: 12/03/2026 अपराह्न 03:00 बजे तक।
05. निविदा खोले जाने की तिथि	: 12/03/2026 सायं 04:00 बजे।
भारत रत्न. स्व. श्री अटल बिहारी वाजपेयी स्मृति शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय संबद्ध चिकित्सालय राजनांदागांव के कक्ष क्रमांक. 26 में।	
संयुक्त संचालक एवं अधीक्षक भारत रत्न. स्व. श्री अटल बिहारी वाजपेयी स्मृति शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय संबद्ध चिकित्सालय राजनांदागांव (छ.ग.)	
जी- 252606877/2	

छत्तीसगढ़ शासन, जल संसाधन विभाग कार्यालय कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, नारायणपुर (छ.ग.)

ई-प्रोक्यूरमेंट निविदा सूचना

eProcurement Portal : <https://eproc.cgstate.gov.in> (द्वितीय आमंत्रण)

डिस्ट्रिक्ट निविदा क्र. 185889/ निविदा सूचना क्र. 12/ वलेलि/2025-26, दिनांक 20.02.2026

निम्नलिखित कार्यों के लिए दिनांक 09.03.2026 17:30 तक ऑनलाइन निविदाएं आमंत्रित की जाती हैं :-

कार्य का नाम : नारायणपुर जिले के विकासखण्ड नारायणपुर में कातुलबेड़ा स्टापडेम का निर्माण कार्य (भाग-2)

अनुमानित लागत : रुपये 35.47 लाख

(छ.ग.) शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा निर्माण एवं संधारण कार्यों हेतु दर अनुसूची 01.11.2021 से प्रभावशील एवं 02/2024 तक संशोधित के आधार पर)

अन्य विवरण एवं विस्तृत निविदा छत्तीसगढ़ शासन की ई-प्रोक्यूरमेंट वेब साइट <https://eproc.cgstate.gov.in> पर नामांकित/पंजीयन तथा लोक निर्माण विभाग की एकीकृत पंजीयन प्रणाली के अंतर्गत ठेकेदार को उपयुक्त श्रेणी में पंजीयन कराना अनिवार्य है।

कार्यालय अभियंता जल संसाधन संभाग नारायणपुर

जी- 252606844/2

पुरी और पुणे के मध्य एक फेरे के लिए स्पेशल ट्रेन का परिचालन

रायपुर (विश्व परिवार)। रेलवे प्रशासन द्वारा यात्रियों की अतिरिक्त भीड़ को नियंत्रित करने तथा उन्हे सुगम, सुरक्षित एवं आरामदायक यात्रा सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से पुरी और पुणे के मध्य एक फेरे के लिए स्पेशल ट्रेन का परिचालन किया जा रहा है। इस गाड़ी का वाणिज्यिक ठहराव दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के रायगढ़, विलासपुर, रायपुर, दुर्ग, एवं गोंदिया स्टेशनों पर दिया गया है।



अनुगुल आगमन 09.55 बजे, प्रस्थान 09.57 बजे, संबलपुर सिटी आगमन 12.20 बजे, प्रस्थान 12.25 बजे, झारसुगुड़ा रोड आगमन 13.30 बजे, प्रस्थान 13.35 बजे, रायगढ़ आगमन 15.13 बजे, प्रस्थान 15.15 बजे, विलासपुर आगमन 18.15 बजे, प्रस्थान 18.25 बजे, रायपुर आगमन 20.05 बजे, प्रस्थान 20.10 बजे, दुर्ग आगमन 21.05 बजे, प्रस्थान 21.10 बजे, गोंदिया आगमन 23.04 बजे, प्रस्थान 23.06 बजे तथा दूसरे दिन नागपुर आगमन 01.10 बजे, प्रस्थान 01.15 बजे, वर्धा आगमन 02.10 बजे, प्रस्थान 02.12 बजे, बडनेरा आगमन 03.15 बजे।

गिरौदपुरी मेले के सफल आयोजन के लिए कलेक्टर ने जताया आभार

बलौदाबाजार - भाटापारा। बाबा गुरु घासीदास जी की पवन जन्मस्थली एवं तपोभूमि गिरौदपुरी धाम में 22 से 24 फरवरी तक आयोजित तीन दिवसीय भव्य संत समागम एवं गुरुदर्शन मेला का गरिमायु और शांतिपूर्ण समापन पर कलेक्टर दीपक सोनी ने अपनी कृतज्ञता व्यक्त की है। कलेक्टर ने मेले को सुव्यवस्थित ढंग से संपन्न करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते वाली मेला समिति, मेला से जुड़े अधिकारी-कर्मचारी एवं दर्शन के लिए आए लाखों श्रद्धालुओं और जिले के नागरिकों के प्रति विशेष रूप से आभार प्रकट किया है। उन्होंने कहा कि आस्था के इस महाकुंभ में सभी के सहयोग से अनुशासन और सुरक्षा का वातावरण बना रहा, जिससे दूर-दराज से आए श्रद्धालुओं को सुलभ दर्शन प्राप्त हुए।

10 नए हाईमास्ट की रौशनी से जगमग होगा रावणभाठा का ऐतिहासिक दशहरा मैदान

रायपुर (विश्व परिवार)। अब राजधानी शहर रायपुर का रावणभाठा में ऐतिहासिक दशहरा मैदान 10 हाईमास्ट की रौशनी से जगमग होगा और वहां रात्रिकालीन धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, खेलकूद एवं अन्य विविध गतिविधियां नियमित रूप से की जा सकेंगी। अधोसंरचना मंडल अंतर्गत नगर पालिक निगम रायपुर के विद्युत विभाग द्वारा 10 नए हाईमास्ट की स्थापना ऐतिहासिक दशहरा मैदान रावणभाठा में की जायेगी। आज महापौर श्रीमती मीनल चौबे ने ऐतिहासिक रावणभाठा दशहरा मैदान पहुंचकर वहां चारों ओर 10 नये हाई मास्ट लगाकर रौशनी बिखेरे जाने नये विकास कार्य का श्रीफल फोड़कर और कुदाल चलाकर भूमिपूजन सहित कार्यांभ नगर निगम एमआईसी सदस्य और रावणभाठा दशहरा मैदान उत्सव समिति अध्यक्ष श्री

स्वच्छ और सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराने लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग प्रतिबद्ध - अरुण साव

उपमुख्यमंत्री ने केमिस्ट के पद पर चयनितों को सौंपे नियुक्ति पत्र

रायपुर (विश्व परिवार)। उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साव ने लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग में केमिस्ट के पद पर चयनित युवाओं को नियुक्ति पत्र प्रदान किए। उन्होंने आज नवा रायपुर में छत्तीसगढ़ विधानसभा परिसर स्थित अपने कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में 10 चयनितों को नियुक्ति पत्र सौंपा। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के सचिव मोहम्मद कैसर अब्दुलहक और प्रमुख अभियंता ऑकेश चंद्रवंशी भी इस दौरान मौजूद थे। उप मुख्यमंत्री तथा लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री अरुण साव ने नव नियुक्त केमिस्टों को संबोधित करते हुए कहा कि केमिस्टों की संख्या बढ़ने से विभागीय जल परीक्षण प्रयोगशालाएं और अधिक सुदृढ़ होंगी तथा मैदानी स्तर पर जल की गुणवत्ता की जांच में सहूलियत होगी। उन्होंने कहा कि प्रदेशवासियों को शुद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण



पेयजल उपलब्ध कराना शासन की प्राथमिकता और प्रतिबद्धता है। इन नियुक्तियों से विभाग में तकनीकी रूप से दक्ष मानव संसाधन की संख्या बढ़ी है। श्री साव ने कहा कि पारदर्शी और निष्पक्ष भर्ती प्रक्रिया से प्रदेश के युवाओं में विश्वास और उत्साह बढ़ा है। युवाओं को उनकी मेहनत और प्रतिभा का उचित प्रतिफल मिल रहा है। उन्होंने उम्मीद जताई कि नवनियुक्त सभी केमिस्ट पूर्ण निष्ठा, अनुशासन और सेवा-भाव के साथ अपने दायित्वों का निर्वहन करेंगे तथा विभागीय लक्ष्यों की प्राप्ति में

सक्रिय भूमिका निभाएंगे। उप मुख्यमंत्री श्री साव ने कहा कि जल गुणवत्ता की निगरानी में किसी प्रकार की शिथिलता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। प्रयोगशालाओं की कार्यप्रणाली को आधुनिक एवं परिणाममुखी बनाया जाएगा। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के प्रमुख अभियंता ऑकेश चंद्रवंशी ने बताया कि विभाग द्वारा स्वीकृत केमिस्ट के 12 पदों पर व्यापक के माध्यम से चयन प्रक्रिया संपन्न की गई थी। दस्तावेज परीक्षण में 11 अभ्यर्थी पात्र पाए गए, जबकि एक अभ्यर्थी अनुपस्थित रहा।

नए विधानसभा भवन में बजट 2026 के ऐतिहासिक सत्र के साक्षी बने मैट्स विश्वविद्यालय के विद्यार्थी



रायपुर (विश्व परिवार)। मैट्स विश्वविद्यालय के अंग्रेजी विभाग के विद्यार्थियों को छत्तीसगढ़ विधान सभा का शैक्षणिक भ्रमण करने तथा माननीय वित्त मंत्री द्वारा प्रस्तुत बजट 2026 को प्रत्यक्ष रूप से देखने का विशिष्ट अवसर प्राप्त हुआ। यह भ्रमण विद्यार्थियों के लिए शिक्षाप्रद और प्रेरणादायक रहा। उन्होंने महत्वपूर्ण बजट सत्र के दौरान विधानसभा की कार्यवाही का ध्यानपूर्वक देखा और समझा। यह अवसर विशेष रूप से महत्वपूर्ण था क्योंकि यह नए विधानसभा भवन में प्रस्तुत किया गया पहला बजट था। विद्यार्थियों के लिए विधानसभा के भीतर उपस्थित होकर

लोकतांत्रिक शासन प्रणाली को प्रत्यक्ष रूप से देखना एक अनूठा अनुभव रहा। इस सत्र ने उन्हें संसदीय प्रक्रियाओं, वाद-विवाद तथा राज्य के बजट की संरचित प्रस्तुति की व्यावहारिक जानकारी प्रदान की। डॉ. रंजना दास शाखेल विभागाध्यक्ष, अंग्रेजी विभाग, ने ऐसे शैक्षणिक भ्रमणों के महत्व पर बल देते हुए कहा कि इससे विद्यार्थियों की शासन व्यवस्था, लोक नीति और नागरिक दायित्वों के प्रति समझ विकसित होती है। उन्होंने बताया कि मैट्स विश्वविद्यालय सदैव कक्षा शिक्षण के साथ-साथ क्षेत्रीय अनुभवों के माध्यम से विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास पर विशेष ध्यान देता है।

छत्तीसगढ़ ने बजट 2026-27 के उद्योग- केन्द्रित प्रावधानों का किया स्वागत

रायपुर (विश्व परिवार)। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा 24 फरवरी को प्रस्तुत बजट 2026-27 में उद्योग क्षेत्र को विशेष प्राथमिकता दिए जाने पर Confederation of Indian Industry (CII) छत्तीसगढ़ राज्य परिषद ने स्वागत व्यक्त किया है। परिषद का मानना है कि यह बजट राज्य के औद्योगिक विकास को नई दिशा और गति प्रदान करेगा। Confederation of Indian Industry (CII) बजट में उद्योग विभाग के लिए कुल 21,750 करोड़ का प्रावधान किया गया है, जो विनिर्माण, उद्यमिता, निर्यात संवर्धन एवं तकनीक-आधारित औद्योगिक विकास को प्रोत्साहन देने की सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। CII छत्तीसगढ़ राज्य परिषद के अध्यक्ष एवं RSV Exim Pvt. Ltd. के प्रबंध निदेशक श्री



संजय जैन ने बजट पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा, उद्योग विभाग के लिए 21,750 करोड़ का आवंटन छत्तीसगढ़ में औद्योगिक विकास को गति देने की दिशा में एक सशक्त एवं दूरदर्शी कदम है। कृषि-आधारित उद्योगों, औद्योगिक अधोसंरचना, निर्यात प्रोत्साहन तथा नवाचार-आधारित मिशनों पर विशेष ध्यान राज्य की

समग्र आर्थिक प्रगति को सुनिश्चित करेगा। उन्होंने विशेष रूप से बस्तर एवं सरगुजा क्षेत्रों में धान मिल, पोलीटी फार्म तथा एग्रो-फारेस्ट प्रोसेसिंग इकाइयों सहित कृषि-आधारित एवं रोजगारोन्मुख उद्योगों के लिए 7100 करोड़ के प्रावधान को सराहना की। उनके अनुसार, इससे संतुलित क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा मिलेगा और स्थानीय स्तर पर बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर सृजित होंगे। CII छत्तीसगढ़ राज्य परिषद के उपाध्यक्ष एवं Shri Bajrang Power & Sapat Ltd. के निदेशक श्री बजरंग गोयल ने कहा, बजट 2026-27 राज्य के लिए एक प्रगतिशील औद्योगिक दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है। कृषि-

आधारित उद्योगों को बढ़ावा देने से ग्रामीण औद्योगिकीकरण को बल मिलेगा। वहीं नवा रायपुर-झुझारना-दामोदर क्षेत्र में अधोसंरचना विकास से राज्य की विनिर्माण प्रतिस्पर्धात्मकता में वृद्धि होगी। उन्होंने आगे कहा कि 7750 करोड़ की सिम्बडी एवं सहायता राशि उद्योगों पर वित्तीय दबाव को कम करेगी और विस्तार योजनाओं को गति देगी। साथ ही स्टार्टअप एवं एआई मिशन के माध्यम से छत्तीसगढ़ को तकनीक-सक्षम एवं भविष्य उन्मुख औद्योगिक राज्य के रूप में विकसित करने की दिशा में ठोस कदम उठाए गए हैं। CII छत्तीसगढ़ ने विश्वास व्यक्त किया है कि बजट के इन उद्योग-केन्द्रित प्रावधानों से निवेश आकर्षण बढ़ेगा, औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि होगी।

अवैध शराब बिक्री पर करारा प्रहार, कबीरधाम पुलिस की लगातार कार्रवाई, शराब के साथ आरोपी गिरफ्तार



सहसपुर लोहरा (विश्व परिवार)। पुलिस अधीक्षक श्री धर्मेन्द्र सिंह द्वारा जिले में सभी प्रकार की अपराधिक गतिविधियों पर प्रभावी अंकुश लगाने हेतु समस्त थाना प्रभारियों को निर्देशित किया गया है। उक्त निर्देशों के परिपालन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पुष्पेन्द्र बघेल एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अमित पटेल के मार्गदर्शन तथा पुलिस अनुविभागीय अधिकारी कृष्ण कुमार चंद्राकर के पर्यवेक्षण में थाना प्रभारी निरीक्षक मनीष मिश्रा के नेतृत्व में दिनांक 24.02.2026 को थाना स. लोहरा पुलिस टीम द्वारा कार्रवाई की गई। कार्रवाई के दौरान मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि शांति नगर, सहसपुर लोहरा मेन रोड किनारे एक व्यक्ति अवैध रूप से शराब रखकर बस के

माध्यम से बिक्री हेतु ले जाने की फिराक में खड़ा है। सूचना की तस्दीक हेतु पुलिस टीम द्वारा मौके पर पहुंचकर घेराबंदी कर सदिश व्यक्ति को पकड़ा गया। पृच्छात ख पर आरोपी ने अपना नाम इमरान खान पिता समशेर अली उम्र 53 वर्ष निवासी रक्से थाना स. लोहरा जिला कबीरधाम (छ.ग.) बताया। आरोपी के कब्जे से एक पीले-लाल रंग के थैले में रखी 36 पौवा देशी मंदिरा प्लेन मंदिरा प्रत्येक शीशी 180 एमएल भरी हुई शीलबंद अवस्था में कुल मात्रा 6.480 बल्क लीटर अनुमानित कीमत 2,880 रुपये जप्त की गई। आरोपी द्वारा शराब बिक्री हेतु परिवहन किया जाना पाया गया। शराब के संबंध में वैध दस्तावेज मांगने पर कोई कागजात प्रस्तुत नहीं किए गए। आरोपी का कृत्य

धारा 34(2) आबकारी एक्ट के अंतर्गत अपराध पाए जाने से मौके पर विधिवत कार्यवाही करते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी की सूचना परिजनों को दी गई। जप्त सामग्री सहित आरोपी के विरुद्ध थाना स. लोहरा में अपराध क्रमांक 22/2026 पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। आरोपी को दिनांक 25.02.2026 को माननीय न्यायालय कवर्धा के समक्ष प्रस्तुत किया गया। प्रकरण में विवेचना जारी है। उक्त कार्यवाही में निरीक्षक मनीष मिश्रा, सजिन संदीप चौबे, सजिन बलदाउ भट्ट, आरक्षक क्रमांक 47, 711 एवं योगदान रहा। कबीरधाम पुलिस द्वारा अवैध गतिविधियों के विरुद्ध अभियान लगातार जारी है।

नल कर का बकाया राशि, नल कनेक्शन काटने की कार्यवाही जारी

राजनदांवांव। वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर नगर निगम द्वारा राजस्व वसूली में कड़ाई बरतते हुये प्रतिदिन कार्यवाही की जा रही है। साथ ही संपत्तिकर के बड़े बकायादारों को नोटिस जारी किया गया है और बकायादारों का नाम प्रकाशित किए जाने की तैयारी है। जल कर के बड़े बकायादारो का नल कनेक्शन काटा जा रहा है। आज की कार्यवाही में पुराना कमल टाकिज रोड एवं नंदई के घरो से 7 नल कनेक्शन काटा गया। वित्तीय वर्ष समाप्ति के अंतिम माह में सतप्रतिशत राजस्व वसूली के लिए महापौर श्री मधुसूदन यादव एवं निगम आयुक्त अतुल विश्वकर्मा राजस्व विभाग की प्रतिदिन मानिटरिंग कर घर घर जाकर कर वसूली करने दिश निर्देश दे रहे है तथा बडे बकायादारो को अपने बकाया करो का भुगतान करने समझाईस दे रहे है।

कार्यालय नगर पालिक निगम, रायपुर (जोन क्र.-1) सतोपी नगर, खतबरगई पानी टकी, रायपुर E-mail ID - rmczone1@gmail.com पत्र क्र./28330/न.पा.नि./जोन क्र.-1/2026 रायपुर, दिनांक 16-02-2026

इशतिहार
नामांतरण प्र.क्र. 28330
वार्ड का नाम- 17 ठक्कर बापा वार्ड
एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि वार्ड 17 स्थित भवन/भूमि जिसका प्रॉपर्टी आई.डी. RPR108B00855 जो कि निगम अभिलेख श्री/श्रीमती M. SINHA NALAM पिता/पति, श्री/श्रीमती के नाम से दर्ज है, जिसको श्री/श्रीमती SHRI MENDA SANTOSH KUMAR पिता/पति, श्री/श्रीमती S/O LATE MENDA SIMHACHALAM ने मृत्यु प्रमाण पत्र, सह पत्र, शपथ पत्र, दान पत्र, हिब्बतनामा, रजिस्ट्री विलेख के अनुसार/ वंशानुक्रम/ अन्य अभिलेख द्वारा प्राप्त नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 को धारा 167 के तहत द्वारा आवेदन किया है। यदि कोई व्यक्ति/संस्था उपरोक्त स्वामित्व परिवर्तन में हक या दावा रखते हैं, प्रकाशन के 15 दिन के भीतर प्रकरण क्रमांक सहित लिखित में अपना दावा/प्रस्तुत करें। निर्धारित समयावधि पश्चात प्राप्त दावा/आपत्ति पर किसी प्रकार की सुनवाई नहीं की जाएगी। जिसके लिए यह कार्यालय जिम्मेदार नहीं होगा।
-सूचना जारी करें-
श्रीमती दिव्या चंद्रवंशी (जोन कमिश्नर)
जोन क्रमांक- (1)
नगर पालिक निगम, रायपुर (छ.ग.)

तृप्ति को मिला अमृत कुंभ सम्मान



राजनदांवांव (विश्व परिवार)। हिंदी भाषा भारतीय संस्कृति, ज्ञान परम्परा और राष्ट्रीय भावना की वह जीवंत धारा है, जिसने देश को एक सूत्र में बांधे रखा है। मातृभाषा के प्रति सम्मान, अभिव्यक्ति में सहजता तथा ज्ञान विस्तार की दृष्टि से हिंदी का योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण रहा है। इस दिशा में हिंदी ओलंपियाड फाउंडेशन द्वारा संचालित गतिविधियां प्रशंसनीय हैं। इसी क्रम में फाउंडेशन द्वारा गत दिनों अमृत कुंभ सम्मान व अंतर्राष्ट्रीय हिंदी

ओलंपियाड पुरस्कार वितरण समारोह सी डी देशमुख ऑडिटोरियम नई दिल्ली में आयोजित किया गया, जिसमें स्थानीय वाइडनर इंग्लिश मीडियम स्कूल की शिक्षिका तृप्ति दुबे को उनकी स्वरचित रचना के लिये अमृत कुंभ सम्मान से सम्मानित किया गया। यह सम्मान उन्हें लड़ाख के उप राज्यपाल द्वारा प्रदान किया गया। तृप्ति की इस उपलब्धि पर विद्यालय परिवार, उनके ईष्ट मित्रों व परिजनों ने बधाई देते हुये शुभकामनायें प्रेषित की हैं।

पहलाजानी केस: आप पार्टी बोली- एफआईआर के बावजूद गिरफ्तारी नहीं हुई

रायपुर (विश्व परिवार) आम आदमी पार्टी ने रायपुर के पहलाजानी टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर का मामला फिर से उठाया है। अस्पताल के खिलाफ एफआईआर दर्ज होने के बावजूद अब तक किसी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। इसको लेकर जांच की रफ्तार और पुलिस कार्रवाई पर आप ने सवाल खड़े किए हैं। मामला दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा जिले के बचेली निवासी दंपती से जुड़ा है। जिन्होंने आईवीएफ प्रक्रिया के जरिए संतान प्राप्ति के लिए सेंटर का रुख किया था। 25 दिसंबर 2023 को ऑपरेशन के माध्यम से जुड़वा बच्चों के जन्म के बाद परिजनों ने बच्चों की अदला-बदली का आरोप लगाया था। परिवार का दावा है कि अस्पताल स्टाफ ने एक बेटा और एक बेटी होने की जानकारी दी

थी, लेकिन बाद में दोनों बच्चियां सौंप दी गईं। संदेह के बाद पिता ने निजी स्तर पर डीएनए जांच कराई और मामला न्यायालय पहुंचा। मामला उच्चतम न्यायालय तक पहुंचा, जहां 19 जनवरी 2026 को एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया गया। हालांकि आरोप है कि आदेश के तुरंत बाद भी एफआईआर दर्ज नहीं की गई और बाद में 6 फरवरी 2026 को मामला दर्ज किया गया। अब एफआईआर दर्ज हुए भी समय बीत रहा है, लेकिन अब तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। आप का कहना है कि, परिवार को अब तक न्याय नहीं मिला है और न ही उनके बच्चे की स्थिति स्पष्ट की गई है। कानूनी जानकारों के अनुसार, सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद दर्ज एफआईआर में देरी और गिरफ्तारी न होना।

कार्यालय नगर पालिक निगम, रायपुर (जोन क्र.-6) आई.एस.बी.टी. चतुर्थ ताल, रावणभाठा, रायपुर Email ID - rmczone6@gmail.com पत्र क्र./28991/न.पा.नि./जोन क्र.-6/2026 रायपुर, दिनांक 25-02-2026

इशतिहार
नामांतरण प्र.क्र. 28991
वार्ड का नाम-65 - महागया मंदिर वार्ड
एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि वार्ड- 65 स्थित भवन/भूमि जिसका प्रॉपर्टी आई.डी. RPR66E2E00184 जो कि निगम अभिलेख श्री/श्रीमती MANOHAR RAO DHIGE पिता/पति श्री/श्रीमती S/O LATE. TULAJI RAO DHIGE के नाम से दर्ज है, जिसको श्री/श्रीमती कल्पना ढिंगे पिता/पति श्री/श्रीमती पति - स्व. श्री मनोहर राव ढिंगे ने मृत्यु प्रमाण पत्र, सह पत्र, शपथ पत्र, दान पत्र, हिब्बतनामा, रजिस्ट्री विलेख के अनुसार/ पंजीकृत हक त्याग विलेख / वंशानुक्रम/ अन्य अभिलेख द्वारा प्राप्त नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 को धारा 167 के तहत द्वारा आवेदन किया है। यदि कोई व्यक्ति/संस्था उपरोक्त स्वामित्व परिवर्तन में हक या दावा रखते हैं, प्रकाशन के 15 दिन के भीतर प्रकरण क्रमांक सहित लिखित में अपना दावा/प्रस्तुत करें। निर्धारित समयावधि पश्चात प्राप्त दावा/आपत्ति पर किसी प्रकार की सुनवाई नहीं की जाएगी। जिसके लिए यह कार्यालय जिम्मेदार नहीं होगा।
-सूचना जारी करें-
श्री हितेन्द्र यादव (जोन कमिश्नर)
जोन क्र.- 6
नगर पालिक निगम, रायपुर (छ.ग.)

कार्यालय नगर पालिक निगम, रायपुर (जोन क्र.-3) शंकर नगर पानी टकी के नीचे, रायपुर E-mail ID - rmczone3@gmail.com पत्र क्र./28971/न.पा.नि./जोन क्र.-3/2026 रायपुर, दिनांक 25-02-2026

इशतिहार
नामांतरण प्र.क्र. 28971
वार्ड का नाम-30 - शंकर नगर वार्ड
एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि वार्ड- 30 स्थित भवन/भूमि जिसका प्रॉपर्टी आई.डी. RPR331E00014 जो कि निगम अभिलेख श्री/श्रीमती SMT. KALPANA RAO पिता/पति श्री/श्रीमती W/O SUDHEER JAIN के नाम से दर्ज है, जिसको श्री/श्रीमती SMT. SARIKA SOMAWAR पिता/पति श्री/श्रीमती W/O AJAY KUMAR SOMAWAR ने मृत्यु प्रमाण पत्र, सह पत्र, शपथ पत्र, दान पत्र, हिब्बतनामा, रजिस्ट्री विलेख के अनुसार/ पंजीकृत विक्रय विलेख / वंशानुक्रम/ अन्य अभिलेख द्वारा प्राप्त नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 को धारा 167 के तहत द्वारा आवेदन किया है। यदि कोई व्यक्ति/संस्था उपरोक्त स्वामित्व परिवर्तन में हक या दावा रखते हैं, प्रकाशन के 15 दिन के भीतर प्रकरण क्रमांक सहित लिखित में अपना दावा/प्रस्तुत करें। निर्धारित समयावधि पश्चात प्राप्त दावा/आपत्ति पर किसी प्रकार की सुनवाई नहीं की जाएगी। जिसके लिए यह कार्यालय जिम्मेदार नहीं होगा।
-सूचना जारी करें-
श्रीमती प्रीति सिंह (जोन कमिश्नर)
जोन क्र.- (3)
नगर पालिक निगम, रायपुर (छ.ग.)

कार्यालय नगर पालिक निगम, रायपुर (जोन क्र.-3) शंकर नगर पानी टकी के नीचे, रायपुर E-mail ID - rmczone3@gmail.com पत्र क्र./28955/न.पा.नि./जोन क्र.-3/2026 रायपुर, दिनांक 25-02-2026

इशतिहार
नामांतरण प्र.क्र. 28955
वार्ड का नाम-30 - शंकर नगर वार्ड
एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि वार्ड- 30 स्थित भवन/भूमि जिसका प्रॉपर्टी आई.डी. RPR331H02334 जो कि निगम अभिलेख श्री/श्रीमती SHREE MADAN CONSTRUCTION PRO. , RAKESH SARAOGI पिता/पति श्री/श्रीमती S/O SATAYANARAYAN SARAWAGI के नाम से दर्ज है, जिसको श्री/श्रीमती SMT. SUMMI SINGH पिता/पति श्री/श्रीमती W/O AJAY KUMAR SINGH ने मृत्यु प्रमाण पत्र, सह पत्र, शपथ पत्र, दान पत्र, हिब्बतनामा, रजिस्ट्री विलेख के अनुसार/ पंजीकृत विक्रय विलेख / वंशानुक्रम/ अन्य अभिलेख द्वारा प्राप्त नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 को धारा 167 के तहत द्वारा आवेदन किया है। यदि कोई व्यक्ति/संस्था उपरोक्त स्वामित्व परिवर्तन में हक या दावा रखते हैं, प्रकाशन के 15 दिन के भीतर प्रकरण क्रमांक सहित लिखित में अपना दावा/प्रस्तुत करें। निर्धारित समयावधि पश्चात प्राप्त दावा/आपत्ति पर किसी प्रकार की सुनवाई नहीं की जाएगी। जिसके लिए यह कार्यालय जिम्मेदार नहीं होगा।
-सूचना जारी करें-
श्रीमती प्रीति सिंह (जोन कमिश्नर)
जोन क्र.- (3)
नगर पालिक निगम, रायपुर (छ.ग.)

कैट नेशनल ट्रेड एक्सपो 2026 का भव्य समापन

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय बोले- छत्तीसगढ़ व्यापार का नया ग्रोथ इंजन

रायपुर (विश्व परिवार)। देश के सबसे बड़े व्यापारी संगठन कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (कैट) के राष्ट्रीय वाइस चेयरमैन एवं राष्ट्रीय व्यापारी कल्याण बोर्ड (भारत सरकार) के सदस्य श्री अमर पारवानी, छत्तीसगढ़ इकाई के चेयरमैन श्री जितेंद्र दोशी, श्री विक्रम सिंहदेव, अध्यक्ष श्री परमानंद जैन, महामंत्री श्री सुरेंद्र सिंह, कोषाध्यक्ष श्री अजय अग्रवाल, कार्यकारी अध्यक्ष श्री राजेंद्र जग्गी, श्री राममंथान, श्री वासु मखोजा, श्री भरत जैन, श्री राकेश ओचवानी तथा श्री शंकर बजाज ने संयुक्त रूप से बताया कि कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (CAIT) द्वारा आयोजित नेशनल ट्रेड एक्सपो 2026 का समापन समारोह अत्यंत भव्य एवं गरिमामय वातावरण में सम्पन्न हुआ। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में माननीय मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी शामिल हुए, जबकि कार्यक्रम की अध्यक्षता राष्ट्रीय व्यापारी कल्याण बोर्ड के चेयरमैन श्री सुनील सिंघो जी ने की। विशिष्ट अतिथि के रूप में महापौर श्रीमती मीनल चौबे की गरिमामयी उपस्थिति रही।



विष्णुदेव साय जी एवं राष्ट्रीय व्यापारी कल्याण बोर्ड के चेयरमैन श्री सुनील सिंघो जी ने कार्यक्रम में मुख्य अतिथि एवं व्यापारिक संगठनों द्वारा उनका भव्य स्वागत गजमाला पहनाकर किया गया। पाँच दिवसीय इस मेले में हजारों की संख्या में नागरिकों, व्यापारियों, युवाओं एवं उद्यमियों ने सहभागिता की। एक्सपो में 250 से अधिक प्रतिष्ठित ब्रांड्स ने भाग लिया, जहाँ आगंतुकों ने नवीन उत्पादों का अवलोकन किया, आवश्यक वस्तुओं की खरीदारी की तथा मैनुफैक्चरर, डिस्ट्रीब्यूटर एवं डीलर्स को

एक सशक्त B2B मंच प्राप्त हुआ। कपड़ा, फूड स्टॉल्स, सांस्कृतिक कार्यक्रमों एवं युवा गतिविधियों ने मंचव को विशेष आकर्षण प्रदान किया। माननीय मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी ने CAIT की पूरी टीम को बधाई देते हुए कहा कि इस प्रकार के एक्जीबिशन प्रदेश के व्यापार और उद्योग को नई गति देते हैं। उन्होंने Expo में प्रदर्शित अनेक नवाचार, AI आधारित समाधान एवं स्थानीय उत्पादों की सराहना करते हुए कहा कि CAIT ने प्रदेश के व्यापारियों को एक सशक्त मंच

प्रदान कर सराहनीय कार्य किया है। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि बोकल फॉर लोकल और स्वदेशी की भावना को मजबूत करने में ऐसे आयोजनों की महत्वपूर्ण भूमिका है। उन्होंने युवाओं की बड़ी भागीदारी को उत्साहजनक बताया है और कहा कि आज का युवा डिजिटल और सोशल युग के माध्यम से प्रदेश के उत्पादों को राष्ट्रीय स्तर तक पहुँचाने में सक्षम है, जिससे रोजगार सृजन और आर्थिक गतिविधियों को बल मिलेगा। उन्होंने हाल ही में घोषित राज्य बजट पर प्रदेशवासियों एवं व्यापारियों को बधाई भी दी।

70वां रेल सप्ताह समारोह 2025, मंडल रेल प्रबंधक स्तर रेल सेवा पुरस्कार

उत्कृष्ट कार्य करने वाले कर्मचारी रायपुर रेल मंडल प्रबंधक दयानंद द्वारा हुए सम्मानित

रायपुर (विश्व परिवार)। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे रायपुर द्वारा आज दिनांक 25 फरवरी, 2025 को उल्लास अधिकारी क्लब, शिवनाथ रेल विहार, डब्ल्यू.आर.एस कॉलोनी, रायपुर में 70वाँ रेल सप्ताह समारोह (मंडल रेल प्रबंधक स्तर)-2025 मुख्य अतिथि मंडल रेल प्रबंधक श्री दयानंद के आतिथ्य में आयोजित किया गया।



भारत में पहली बार रेल का शुभारंभ 16 अप्रैल 1853 में मुंबई से थाणे के मध्य रेल चलाकर की गई थी। इस ऐतिहासिक घटना की याद में रेल मंत्रालय सहित सभी क्षेत्रीय रेलवे, वर्कशॉप, यूनिटों एवं मंडलों में प्रति वर्ष रेल सेवा पुरस्कार मनाया जाता है। 70वाँ रेल सप्ताह समारोह 2025 में रेल कर्मचारियों को उनके द्वारा किये गये उत्कृष्ट कार्यों के लिए उन्हें प्रोत्साहन स्वरूप पुरस्कार दिया गया। 70वाँ रेल सप्ताह समारोह के अवसर पर सर्वप्रथम मुख्य अतिथि मंडल रेल प्रबंधक श्री दयानंद का स्वागत वरिष्ठ मंडल कार्मिक अधिकारी श्री राहुल गर्ग द्वारा किया गया। अतिथियों द्वारा देवी सरस्वती की प्रतिमा पर माल्यार्पण, श्लोक उच्चारण एवं दीप प्रज्वलित कर इस समारोह का शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर वरिष्ठ मंडल

कार्मिक अधिकारी श्री राहुल गर्ग ने स्वागत संबोधन में कठिन परिश्रम, लगन और निष्ठा की बंदीलत उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए पुरस्कार प्राप्त करने वाले कर्मचारियों को बधाई दी। मुख्य अतिथि मंडल रेल प्रबंधक श्री दयानंद ने अपने उद्बोधन में कहा कि भारतीय रेल नेटवर्क, टीम वर्क का श्रेष्ठ उदाहरण है। इस वृहत प्रणाली को गतिमान रखने में रेलवे के सभी विभागों के कर्मचारियों एवं

उपलब्धियों का श्रेय हमारे अधिकारियों के कुशल मार्गदर्शन एवं कर्मचारियों के कठिन परिश्रम को जाता है। हम इसी सेवा भावना एवं कर्तव्य निष्ठा के साथ अपनी ड्यूटी का निर्वहन करते रहेंगे। साथ ही अन्य कर्मचारियों को पुरस्कार प्रदान करने के लिए अपनी पूरी लगन एवं निष्ठा के साथ कार्य करते रहने के लिए प्रेरित किया।

70 वॉ रेल सप्ताह समारोह के अवसर पर मंडल रेल प्रबंधक द्वारा उत्कृष्ट कार्य निष्पादन के लिए 33 कर्मचारियों को व्यक्तिगत पुरस्कार एवं 27 विभागीय शीलड पुरस्कार प्रदान किए गए। साथ ही साथ कार्यरत स्वच्छता कर्मियों को भी पुरस्कृत किया गया। रेल कर्मियों द्वारा तैयार किये गये रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किये गये। पुरस्कार वितरण के पश्चात् सहायक कार्मिक अधिकारी ने धन्यवाद ज्ञापित किया। इस अवसर पर अध्यक्ष सेक्री श्रीमती शिखा सिंह, अपर मंडल रेल प्रबंधक श्री बजरंग अग्रवाल, रायपुर मंडल के वरिष्ठ अधिकारी एवं समस्त यूनियन एवं एसोसिएशन के पदाधिकारियों सहित रेल कर्मचारीगण उपस्थित थे। 70 व रेल सेवा पुरस्कार 2025 में रायपुर रेल मंडल के विभागों को दक्षता अवाड शीलड दिया गया।

विसः नल जल योजना, रोजगार सहित उद्योग व महिला श्रमिकों के हित का उठाया मुद्दा

रायपुर (विश्व परिवार)। पंडरिया विधायक भावना बोहरा द्वारा विधानसभा में जनहित व प्रदेश के प्रमुख विषयों से जुड़े प्रश्न लगातार विधानसभा पटल पर रखे रहें हैं। बजट सत्र के तीसरे दिन उन्होंने नल जल योजना से जल आपूर्ति व गर्मी के दिनों में ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में पर्याप्त जल आपूर्ति के लिए प्रशासन द्वारा की गई तैयारियों, इन्वेस्ट कनेक्ट और स्थानीय रोजगार एवं कबीरधाम जिला में संचालित लघु व मध्यम उद्योग को प्रोत्साहन और महिला श्रमिकों के हित के सन्दर्भ में प्रश्न पूछा।



पंडरिया विधायक भावना बोहरा ने प्रश्न किया कि पिछले 12 महीनों में कितने जिलों/शहरों में नल जल योजना को जोड़ लिया गया है? कितने जिलों में योजना पूर्ण कर ली गई है? बचे हुए जिलों में कब तक यह योजना पूर्ण कर ली जाएगी? वर्तमान में छत्तीसगढ़ नल जल योजना की लक्ष्य पूर्ति में किस स्थान पर है? तथा आगामी ग्रीष्मकाल में शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में जल आपूर्ति के लिए विभाग की क्या योजना है? जिसके लिखित प्रतिउत्तर में उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साव जी ने बताया कि पिछले 12 महीनों में राज्य के सभी जिलों के ग्रामीण क्षेत्रों को नल जल योजना से जोड़ लिया गया है। शहरों में नल जल योजना लागू नहीं है। शहरों के किसी भी जिला में योजना पूर्ण नहीं की गई है। संभावित तिथि बताना संभव नहीं है।

ऑल-न्यू निसान ग्रेविट 5.65 लाख रुपये की शुरुआती कीमत पर हुआ लॉन्च

रायपुर (विश्व परिवार)। शिवा निसान ने आज ऑल-न्यू निसान ग्रेविट को 5.65 लाख रुपये की आकर्षक शुरुआती कीमत पर लॉन्च करने की घोषणा की। एक दमदार और क्रांतिकारी 7-सीटर एमपीवी, ग्रेविट निसान के भारत सफर में एक नए अध्याय की शुरुआत है। भारत से प्रेरित, भारत में निर्मित, भारत के लिए निर्मित, ग्रेविट निसान मोटर इंडिया के नए उत्पाद अभियान के तहत लॉन्च होने वाला पहला उत्पाद है - जो भारत में कंपनी की मजबूत प्रतिबद्धता और उपस्थिति को रेखांकित करता है। ग्रेविट नाम 1.4 अरब भारतीयों और 19,000 स्थानीय भाषाओं और रीति-रिवाजों से प्रेरित है जो देश की विविधता को आकार देते हैं। ग्रेविट को भारतीय परिवारों की बदलती आकांक्षाओं



को पूरा करने के लिए विशेष रूप से बनाया गया है। यह दमदार उपस्थिति के साथ जगह, बहुमुखी प्रतिया, आराम और रोजमर्रा की व्यावहारिकता का संयोजन करता है। ऑल-न्यू निसान ग्रेविट निसान की वैश्विक डिजाइन भाषा के अनुरूप एक विशिष्ट और आत्मविश्वासपूर्ण पहचान स्थापित करती है। इसके ऊंचे अनुपात, मस्कूलर बॉडी लाइन्स, उभरे हुए व्हील

आर्च और उच्च ग्राउंड क्लियरेंस इसे एक दमदार रोड प्रेजेंस प्रदान करते हैं, जो भारत की विभिन्न ड्राइविंग स्थितियों के लिए उपयुक्त है। ग्रेविट अपने सेगमेंट में एकमात्र वाहन है जिसमें विशिष्ट हुड ब्रांडिंग के साथ-साथ अद्वितीय रियरडोर बैजिंग भी है - एक बोटड डिजाइन अभिव्यक्ति जो विशिष्टता और मजबूत दृश्य स्मृति को मजबूत करती है।

रायपुर (विश्व परिवार)। यूको बैंक की छत्तीसगढ़ राज्य में 63 वीं शाखा के रूप में भाटागांव शाखा, रायपुर का शुभारंभ आज दिनांक- 25.02.2026 को माननीय उप मुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा जी के करकमलों द्वारा संपन्न किया गया। कार्यक्रम में अंचल प्रमुख सुश्री वीणा कुमारी, उप अंचल प्रमुख श्री अमोल बी. मंडारे तथा यूको बैंक के अन्य अधिकारी एवं कर्मचारीगण उपस्थित थे। नई शाखा व्यवसायीक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण स्थान पर स्थित है। शाखा के समीप बस स्टेंड, सब्जी मंडी एवं प्रमुख आवासीय क्षेत्र स्थित है, जिससे क्षेत्र के व्यापारियों, स्थानीय नागरिकों एवं परिवारों को बैंकिंग सेवाओं का सीधा लाभ मिलेगा। बैंक प्रबंधन ने विश्वास व्यक्त



किया है कि इस पहल से क्षेत्र में वित्तीय समावेशन को और अधिक मजबूती मिलेगी तथा अधिकतम लोगों को आधुनिक बैंकिंग सुविधाएं प्राप्त होंगी। इस अवसर पर का अंचल प्रमुख सुश्री वीणा कुमारी ने आश्वस्त किया कि जिस तरह छत्तीसगढ़ राज्य प्रगति की ओर अग्रसर है उसी प्रकार यूको बैंक भी अपना योगदान देने के लिए प्रतिबद्ध है।

क्षेत्र में और एक शाखा इसी वित्तीय वर्ष में पदनाभपुर क्षेत्र में खुल रही है और छत्तीसगढ़ के अन्य सभी जिलों में शाखा खोले जाने का प्रस्ताव विचाराधीन है। जिसे आगामी वित्तीय वर्ष में पूरा करने की योजना है। बैंक ने सभी प्राहकों, शुभचिंतकों तथा भागीदारों से निवेदन किया है कि नई शाखा के कारोबार वृद्धि में अपना सक्रिय योगदान दें।

चलती ट्रेन में कर रहे थे शराब सेवन, यात्रियों के खिलाफ की गई कानूनी

रायपुर (विश्व परिवार)। दिनांक 21.02.2026 को नौतनवा से चलने वाली ट्रेन संख्या 18206 नौतनवा दुर्ग एक्सप्रेस में श्रीमती उषा शुक्ला, लगभग 68 वर्ष की वरिष्ठ नागरिक महिला यात्री, जो अपने बुजुर्ग पति के साथ ट्रेन संख्या 18206 के कोच संख्या ए। सीट संख्या 7-9 में 22.02.2026 को अयोध्या से रायपुर जा रही थीं, की शिकायत प्राप्त हुई थी। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे रायपुर रेल मंडल के वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक श्री अवधेश कुमार त्रिवेदी के निर्देशन पर की गई प्रारंभिक जांच से पता चला है कि भाटापारा से रायपुर के मध्य चलती ट्रेन में श्री प्रवीण सिंह



(ए। कोच की सीट संख्या 24 के यात्री) और श्री गोपाल कासेर (ए2 कोच की सीट संख्या 14 के यात्री) ए। कोच के कार्डिडोर अटेंडेंट कैबिनेट में खुलेआम शराब का सेवन करते पाए गए, जो ट्रेन के भीतर एक सार्वजनिक स्थान है। ए। और ए2 कोच के अटेंडेंट भी इस कृत्य के साक्षी थे। रेलवे के मौजूदा नियमों और

कानून के प्रासंगिक प्रावधानों, जिनमें रेलवे अधिनियम की धारा 145 भी शामिल है, के तहत ऐसा कृत्य सख्त वर्जित है। यह भी पाया गया है कि उपर्युक्त दोनों यात्री शराब के नशे में थे और उन्होंने वरिष्ठ नागरिक महिला यात्री के साथ दुर्व्यवहार किया, जिससे बुजुर्ग पति को मानसिक उत्पीड़न, असुविधा और असुरक्षा की भावना का सामना करना पड़ा। ए। कोच की सीट संख्या 24 पर, जो श्री प्रवीण सिंह के लिए आर्बिट बर्थ थी, शराब से संबंधित सामग्री भी पाई गई, जो इस बात की पुष्टि करती है।

महापौर परिषद में जनहितैषी प्रस्तावों को मिली स्वीकृति

भिलाईनगर (विश्व परिवार)। नगर पालिक निगम भिलाई के महापौर परिषद की बैठक महापौर नीरज पाल की अध्यक्षता एवं आयुक्त राजीव कुमार पाण्डेय की उपस्थिति में ली गई। बैठक में प्रमुख रूप से बैंकहो लोडर क्रय, सर्विस रोड निर्माण एवं प्रधानमंत्री आवास योजना के प्रस्ताव को महापौर परिषद के सदस्यों के समक्ष प्रस्तुत किया गया। 15वें वित्त आयोग के तहत 5 नग बैंकहो लोडर क्रय कार्य हेतु मेमर्स जी.के.आटोव्हील प्रा.लि.रायपुर द्वारा प्रस्तुत न्यूनतम दर 25 लाख रुपये प्रति नग के अनुसार कुल 1 करोड़ 25 लाख रुपये मात्र की स्वीकृति सर्वसम्मति से की गयी। जोन-3 अंतर्गत जो.ई.रोड के



समानांतर चंद्रा मौर्या टाकिंग से नगर निगम जोन-3 कार्यालय के सामने से बजाज शोरूम तक सर्विस रोड निर्माण कार्य हेतु महापौर परिषद की बैठक में चर्चा कर सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की गयी। प्रधानमंत्री आवास योजना सबके लिये आवास मिशन, एएचपी घटक अंतर्गत समय पर 90 प्रतिशत राशि जमा

करने वाले हितग्राहियों को 10 प्रतिशत अंशदान गरीबों की सेवा निधि से प्रदान करने विषयक प्रस्तुत किया गया था। किंतु महापौर परिषद में लिये निर्णय अनुसार इस राशि का उपयोग गरीबों तथा गंदी बस्ती के निवासियों को जलापूर्ति एवं अन्य आवश्यक सेवा प्रदान करने हेतु निर्णय लिया गया।

संरक्षा कार्य के चलते कुछ गाड़ियों का परिचालन रहेगा प्रभावित

रायपुर (विश्व परिवार)। रेलवे प्रशासन द्वारा संरक्षा एवं ट्रैक अनुरक्षण कार्यों को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जा रही है। इसी क्रम में दक्षिण पश्चिम रेलवे के हुबबलि मंडल के कैसलरॉकडुकुलें घाट सेक्शन में लाइन ब्लॉक लेकर बीसीएम (Ballast Cleaning Machine) के माध्यम से ट्रैक अनुरक्षण एवं ट्रैक रिन्वूअल का कार्य किया जाएगा। इस कार्य के फलस्वरूप दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे से संबंधित निम्नलिखित गाड़ियों का परिचालन आंशिक रूप से प्रभावित रहेगा। दिनांक 27 अप्रैल, 04, 11, 18 व 25 मई

तथा 01 जून 2026 को जसीडीह से चलने वाली गाड़ी संख्या 17322 जसीडीह-वास्को द गामा एक्सप्रेस, हुबबलि जंक्शन स्टेशन में समाप्त होगी तथा हुबबलि जंक्शन से वास्को द गामा स्टेशनों के मध्य रह रहेगी। दिनांक 01, 08, 15, 22 व 29 मई तथा 05 जून 2026 को वास्को द गामा से चलने वाली 17321 वास्को द गामा-जसीडीह एक्सप्रेस, वास्को द गामा के बजाय हुबबलि जंक्शन स्टेशन से प्रारम्भ होगी तथा वास्को द गामा से हुबबलि जंक्शन स्टेशनों के मध्य रह रहेगी।

राजधानीवासी खारून का दूषित पानी पीने के लिए मजबूर, विधानसभा में विधायक मूत ने उठाया मुद्दा

रायपुर (विश्व परिवार)। विधानसभा में आज राजधानीवासियों को खारून का दूषित पानी पीने के लिए मजबूर करने वाले देषियों अधिकारियों पर कार्यवाही की मांग को लेकर विधायक राजेश मूत ने विधानसभा में नगरीय प्रशासन मंत्री अरुण साव को घेरा। उन्होंने आरोप लगाया कि खारून नदी के पास एचटीपी लगाने के लिए सरकारी जमीन को छोड़कर अन्य जगह लगाया जा रहा है। जिसके कारण

खारून नदी प्रदूषित हो रही है। नगरीय निकाय मंत्री अरुण साव ने कहा कि खारून नदी के पास 81 करोड़ रूपए खर्च कर 75 एमएलडी क्षमता का एचटीपी का निर्माण किया गया है। चिंगरी नाला का दूषित जल नाले में बनाए गए पीकअपएयर से ओव्हर फ्लो होकर नदी में प्रवाहित हो जाता है। चिंगरी नाला का लाइनिंग एवं अप्रोच नहीं होने तथा फिल्टर की सफाई की समस्या का समाधान करना ही सार्वजनिक वास्तव्य निर्मित हो रही है।



विधायक राजेश मूत ने आरोप लगाया कि 11 एकड़ शासकीय जमीन में यह प्लांट लगाया जाना था, लेकिन इसे अन्यत्र लगा दिया गया है। ऐसे दोषी अधिकारी पर

क्या कार्यवाही की जाएगी। नगरीय निकाय मंत्री अरुण साव ने बताया कि मुख्य अभियंता नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई है। इसके संशोधित प्रस्ताव आने के बाद आगामी कार्यवाही की जाएगी। राजेश मूत द्वारा पूछे गए प्रश्न का समय सीमित होने के कारण ज्यादा कुछ नहीं पूछ पाए। सभापति धरम लाल कौशिक ने उन्हें बोलने का अवसर दिया। राजेश मूत ने कहा कि चिंगरी और पीहर् नाले से नंग

पानी आने के कारण खारून नदी का जल प्रदूषित हो रहा है। दूषित पानी को नदी में जाने से रोकने के लिए 11 करोड़ की कार्ययोजना बनाई गई है, जो कि पिछले एक वर्ष से लंबित है। सक्ती में एचटीपी संयंत्र लगाने की निविदा स्वीकार की जाएगी- अरुण साव नेता प्रतिपक्ष डॉ. चरण दास महंत द्वारा पूछे गए प्रश्न के उत्तर में अरुण साव ने बताया कि सक्ती में स्वच्छ भारत मिशन के तहत एचपीटी के निर्माण के लिए निविदा को स्वीकृति प्रदान की जाएगी।

डिप्लस
कॉस्मेटिक
सर्जरी द्वारा
गालों में
स्थायी
डिप्लस

कालड़ा बर्न एवं
प्लास्टिक कॉस्मेटिक सर्जरी सेंटर

फोन नं.: 9827143060/8871003060

RAIPUR BUSINESS HUB

ITR फाईल बनवाएं मात्र 500/-

GST रजिस्ट्रेशन TDS रिफंड
CMA DATA BALANCE SHEET
MSME रजिस्ट्रेशन फूड लाइसेंस
प्रोजेक्ट रिपोर्ट TAX AUDIT

हमारे TAX EXPERT आपकी मदद हेतु तैयार हैं
(व्हाट्सएप पर भी बनवाएं)

संपर्क - शेखर गुप्ता 9300755544, 8878655544